₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

मार्च 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

आईजीआईएमएस के रग-रग में भ्रष्टाचार

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVPNO:-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

TATA STEEL
#WeAlsoMakeTomorrow
TATA TISCON
JOY OF BUILDING
समझदार
बनें।
बेहतर
चुनें।
बेहतर ताक़त
550MPa ग्रेड स्टील
बेहतर लचक
उच्चतम UTS/YS अनुपात
बेहतर बचत
रीबार का कम इस्तेमाल
TATA
TISCON 550SD
CALL 1800 108 8282

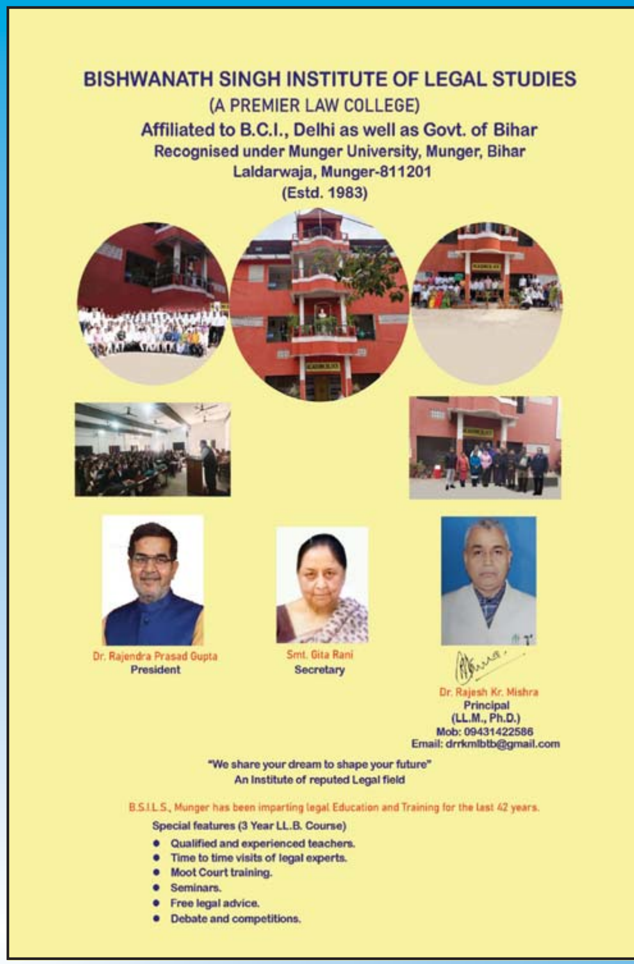

BISHWANATH SINGH INSTITUTE OF LEGAL STUDIES
(A PREMIER LAW COLLEGE)
Affiliated to B.C.I., Delhi as well as Govt. of Bihar
Recognised under Munger University, Munger, Bihar
Laldarwaja, Munger-811201
(Estd. 1983)
Dr. Rajendra Prasad Gupta
President
Smt. Gita Rani
Secretary
Dr. Rajesh Kr. Mishra
Principal
(LL.M., Ph.D.)
Mob: 09431422586
Email: drrkmlbtb@gmail.com
"We share your dream to shape your future"
An Institute of reputed Legal field
B.S.I.L.S., Munger has been imparting legal Education and Training for the last 42 years.
Special features (3 Year LL.B. Course)
Qualified and experienced teachers.
Time to time visits of legal experts.
Moot Court training.
Seminars.
Free legal advice.
Debate and competitions.

स्वच्छ हिलसा, सुन्दर हिलसा
कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा)
नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
जीवेश मिश्रा
मंत्री, नगर विकास एवं
आवास विभाग, बिहार सरकार
ईद, चैती छठ्
एवं रामनवमी के
पवित्र अवसर
पर समस्त
नगरवासियों
को
हार्दिक
शुभकामनाएँ।
धनंजय कुमार
मुख्य पार्षद
नगर परिषद, हिलसा (नालंदा)
श्रीमती दुर्गा कुमारी
उप मुख्य पार्षद
नगर परिषद, हिलसा (नालंदा)

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

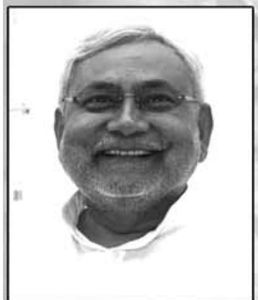

नीतीश कुमार
01 मार्च 1951

मेरी कॉम
01 मार्च 1983

शंकर महादेवन
03 मार्च 1967

शिवराज सिंह चौहान
05 मार्च 1959

अनुपम खेर
07 मार्च 1955

नवीन जिंदल
09 मार्च 1970

उमर अब्दुल्लाह
10 मार्च 1970

श्रेया घोषाल
12 मार्च 1984

वरूण गांधी
13 मार्च 1980

अमीर खान
14 मार्च 1965

हनी सिंह
15 मार्च 1984

राजपाल यादव
16 मार्च 1971

सानिया नेहवाल
17 मार्च 1990

रानी मुखर्जी
21 मार्च 1978

स्मृति जुबैद ईरानी
23 मार्च 1976

इमरान हाशमी
24 मार्च 1979

मधु
26 मार्च 1972

प्रकाश राज
26 मार्च 1965

शीला दीक्षित
31 मार्च 1938

मीरा कुमार
31 मार्च 1945

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कंपनी बनाम पदाधिकारी

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

आजादी के बाद भ्रष्टाचार देश के लिए एक गहरी समस्या है, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में रुकावट डालता है। यह सत्ता, धन और संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में सामने आता है जिससे भ्रष्ट लोगों का बड़ा बाजार को उजागर करना न्यायालय के लिए भी बड़ी चुनौती है। अपनी पद और प्रभाव की स्थिति का गलत फायदा उठाकर कानून और नैतिकता को तोड़ते हैं और सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी क्षेत्र तक, भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है। सरकारी भ्रष्टाचार के रूपों में भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी, पैरवी, गबन और भाई-भतीजावाद शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों को उच्च पद दिलाने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) में 180 देशों में से भारत 96वें स्थान पर है। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार, और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार को अपना औजार बनाया और घूस देने की प्रथा प्रारम्भ की। स्वतंत्रता के पश्चात् 75 वर्षो में भ्रष्टाचार की व्यापकता ने तो इस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को ही निगल डाला। तीव्रता से देश का विकास की चाहत ने लोगों का सुकून भी छीन लिया है तथा आवाम के टैक्स का भी भयंकर रूप से लूटा जा रहा है। केन्द्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार वह अब स्थायी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी भी दे रही है तथा जनबुनियादी सुविधाओं का भी काम किसी न किसी कंपनी के माध्यम से कर रही है। पदाधिकारी से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी कंपनी के द्वारा नियुक्त हो रही है और इस काम को देने वाले विभाग के पदाधिकारी का व्यक्तिगत खजाना भरता जा रहा है। वाहन, वाहन चालक से लेकर हर छोटी-बड़ी कार्य को भी आउटसोर्स कंपनी के द्वारा ही कार्य लिया जा रहा है। किसी भी सरकारी विभाग में किसी प्रकार की सप्लाई से लेकर नौकरी तक के कार्य और देश-विदेश की कंपनियों के द्वारा सरकार के सभी कार्यों में प्रवेश करने की वजह से प्राईवेट कंपनियों की धाक सरकार से ज्यादा होती जा रही है और पदाधिकारी के साथ मिलीभगत करके कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट की लागत बढ़वा देती है और अपनी कंपनी पर काम उठा लेती है। सरकार भी सरकारी नौकरी देने के बजाय कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर नौकरी, निर्माण, सहित हर प्रकार का सेवा दे रही है। सरकार के पदाधिकारी अपना व्यक्तिगत खजाना भरने के चक्कर में ईडी, सीबीआई, निगरानी, आर्थिक अपराध इकाई के गिरफ्त में जा चुके हैं और शेष अधिकारी जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वह खुल्लेआम लाईजनिंग का काम कर रहे हैं। बिचौलिए बड़े प्रोजेक्ट पर प्वाइंट 5 प्रतिशत तो छोटे प्रोजेक्ट पर 01 प्रतिशत का कमीशन बीच का आदमी ले रहा है और पदाधिकारी महंगे फ्लैट और प्रोजेक्ट में अपनी पत्नी और बच्चों का पार्टनर भी बन उनके प्रोजेक्ट को पास कर रहे हैं। एल 01 कराने से लेकर बिल भुगतान तक का जुगाड़ चल रहा है और बैंक से लोन का खेल भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है और इनसब पर आवाज उठाने वाला विपक्ष भी इस खेल में अपना कमीशन लेकर मौन धारण कर लेते हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी भ्रष्टाचार उजागर करने के बजाय विपक्ष तरफ चुप होकर कंपनी और पदाधिकारी के बीच का मजबूत डोर बनकर अपना हिस्सा लेकर मुद्दा को गौण कर देते हैं।

डीजीटल भारत में तेज गति से हो रहे विकास में बिचौलिए की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि केन्द्र एवं राज्य की सरकारें कंपनी और पदाधिकारियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी रखी जा रही है। भवन निर्माण, पथ निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य के साथ सप्लाई और अन्य कार्यों के निविदा में कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। कंपनी और पदाधिकारी के बीच की मजबूत कड़ी की भूमिका का निर्वहन लाईजिंग करने वाले समूहों के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के तरफ से लाईजनिंग ऑफिसर नियुक्त होते हैं लेकिन पदाधिकारी के तरफ जेटीसी ग्रुप का कोई भी सदस्य (लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ का) भाग लेता है और कैसे एल- 01 होगा उसका पूरा जुगाड़ किया जाता है। काम दिलाने से लेकर बिल भुगतान तक की व्यवस्था कमीशन के आधार पर तय किया जाता है। कंपनी बनाम पदाधिकारी के इस खेल में सरकार अपने विभिन्न विभाग में भी कंस्लटेंट भी रखती है ताकि अन्य राज्यों से कंपनी को लाकर विकास की कहानी को भी लिखा जा सके और बिना शोर-शराबे के निविदा का पूरा खेल को अंजाम दे दिया जाता है। बिना बिचौलिए के किसी भी प्रकार का काम चाहे मंत्रालय हो या विभाग या फिर पंचायत सरकार नहीं किया जा सकता। 01 प्रतिशत का कमीशन भी करोड़ों में होता है और इसपर नकेल कसना भी मुश्किल....

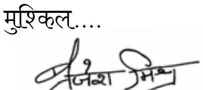

फरवरी 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :- **द्वारा:- ब्रजेश मिश्र**

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

दिल्ली का मालिक

ब्रजेश जी,

मुद्दों की नहीं मुफ्तों की जीत है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर संजय सिन्हा की खबर ''**दिल्ली का मालिक धड़ाम**'' में अरबिन्द केजरीवाल का अंहकार और भाजपा का राजनीतिक दांव-पेंच और मुद्दे को दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली का मालिक अब आप नहीं भाजपा बन चुकी है। 10 साल आपकी सरकार ने मुफ्त में दिल्ली को कहां पहुंचा दिया है पर पूरी गंभीरता से चोट करते हुए पूरी बात को पाठकों को समक्ष रखा है वह पठनीय है। अच्छी खबर है।

✦नारायण पाठक, सेक्टर-4, फरीदाबाद

महाकुंभ

ब्रजेश जी,

फरवरी 2025 अंक केवल सच पत्रिका में प्रकाशित आपका संपादकीय ''**प्रयागराज में सनातन का महाकुंभ**'' में आपने आजादी के बाद सनातन धर्म की एक सुनामी का माहौल बन गया है के विषय को पूर्ण बेबाकी से लिखा है तथा महाकुंभ को लेकर सत्ता एवं विपक्ष द्वारा हुई राजनीति को भी सही ढ़ंग से उकेरा है। भाजपा और खासकर योगी-मोदी की जोड़ी ने भारत में हिन्दुओं की औकात क्या है पूरे विश्व को एहसास करा दिया है। इस महाकुंभ ने हिन्दुओं को एकजुट करके यह साबित कर दिया है हम एक हैं।

✦ सुरेन्द्र चौरसिया, अस्सी घाट, बनारस

झारखंड की खबरें

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के फरवरी 2025 अंक में बिहार, यूपी और दिल्ली सहित झारखंड की भी कई महत्वपूर्ण खबरों को पूर्ण स्थान दिया है और राजनीतिक खबरों को भी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया जा रहा है जो स्वागतयोग्य है। गुड्डी साव की राजनीति से जुड़ी खबरों के साथ-साथ सरकार एवं उसके विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को भी स्थान दिया गया है और पुलिस-प्रशासन की खबरों को पाठकों के समक्ष रखा गया है। बिहार की तरह झारखंड के विभाग के काली करतूतों को भी पुरजोर ढ़ंग से प्रकाशित करके पाठकों के बीच लाना चाहिए।

✦ राकेश तिवारी, खेलगांव, रांची

उजागर करती खबर

मिश्रा जी,

फरवरी 2025 अंक में शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला की पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग का पोल खोलती खबर को पाठक एवं सरकार सहित विभाग के संज्ञान में लाकर सबको सोचने पर विवश कर दिया गया है। ''मंत्री और सचिव हुए पस्त'' वाली खबर में पर्यटन विभाग के पर्यटन निगम में चल रहे गोरखधंधे को उजागर करके अपनी जान जोखिम में डाल ली है, वहीं दूसरी खबर में आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल की खबर भी आपको टारगेट करेगा और राज्य स्वास्थ्य समिति भी उजागर करती खबर से बेहद परेशान होगी। राज्य सरकार को ऐसी खबरों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

✦ पप्पू यादव, पाया नं.-10, राजाबाजार, पटना

विशाल आयोजन

संपादक जी,

बेबाक एवं निर्भिक खबरों के लिए केवल सच पत्रिका पाठकों के बीच खास स्थान रखता है। फरवरी 2025 अंक में यूपी के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर अमित कुमार की खबर ''**संकल्प से ही संभव महाकुंभ का विशाल आयोजन**'' में सभी पहलुओं पर सटीक समीक्षा करती है और उपलब्धियों सहित कुव्यवस्था पर भी चोट करती है और पूरी निष्पक्षता के साथ इस विशाल आयोजन के सभी अनछुए पहुलओं पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराया है। बड़ी खबर होने के बाद भी पढ़ने की उत्सुकता बरकरार है इस खबर में। खबर के लिए बधाई।

✦ सोहन चटर्जी, बहु बाजार, कोलकाता

पतन

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूं और इसके सभी खबरों को पढ़ता हूं लेकिन कुछ खबरें अखबार की खबर जैसी लगती है जिसपर सुधार की आवश्यकता है। फरवरी 2025 अंक की अजय कुमार की खबर ''**कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों में भी पतन का दौड़**'' और ''**यूपी की नई आबकारी नीति, एक तीर से कई निशाने**'' में देश कर विपक्ष की राजनीति सहित यूपी का पूरा खेल भी समझाने की सार्थक कोशिश की गई है। केन्द्र सरकार पर भी फोकस करते हुए अंदर की खबरों को भी पाठकों के समक्ष लाना चाहिए।

✦ कमलेश सिन्हा, सिन्हा कॉलोनी, प्रयागराज

अन्दर के पन्नों में

कोयला कारोबारी पर फायरिंग 85

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्षः- 19,	अंकः- 226,	माहः- मार्च 2025,	मूल्यः- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204
सुरजीत तिवारी 9431222619
निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917
रामानंद राय 9905250798
डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350
अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय 7488696914
ललन कुमार 7979909054, 9334813587
पंकज कुमार सिंह 9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078
संतोष कुमार यादव 8210487516,

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565
काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829
अविनाश कुमार 7992258137, 9430985773
कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994
ऋषिकेश पाण्डेय 7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485
रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976
आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	7004761573
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:- .		
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
.................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

.................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....

....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

....

....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983,
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा कुमार	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	629970142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

आईजीआईएमएस के रग-रग में भ्रष्टाचार

डॉ० मनीष मंडल, डॉ० राजेश कुमार सिंह, परवेज अहमद खान, शैलेन्द्र कुमार सिंह, अनिल कुमार चौधरी जैसे भ्रष्टाचारी आईजीआईएमएस को कर रहे हैं खोखला

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

'बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा?' जैसे टोकरी में एक सड़ा आम पूरी टोकरी के आम को सड़ा देता है, वैसे ही आईजीआईएमएस के पूरे सिस्टम को अधीक्षक मनीष मंडल के मजबूत भ्रष्टाचारी पंजे ने जकड़ लिया है। ऑउटसोर्सिंग तकनीकी-गैर तकनीकी कर्मी की बहाली में घोटाला, अस्पताल की बिल्डिंग बनाने में घोटाला, अधीक्षक बनाने में घोटाला, लिवर ट्रांसप्लांट में घोटाला, हाउसकिपिंग में घोटाला, राज्य कैंसर संस्थान में घोटाला, पौधारोपन में घोटाला, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र घोटाला, सागर-सारण मेडिकल हॉल घोटाला, सुरक्षा गार्ड घोटाला, बायोमेडिकल घोटाला, हॉस्पिटल फर्निचर घोटाला, दवा घोटाला, ओ.पी.डी. में पेसेन्ट भेजने में घोटाला, आई.सी.यू. बेड एलॉटमेन्ट में घोटाला, मरीज भर्ती घोटाला...। ये लिस्ट इतनी लम्बी है कि पूरी पत्रिका के हर पन्ने पर सिर्फ आईजीआईएमएस का घोटाला ही छप जाये। आईजीआईएमएस निविदा संख्या-01/Tender (Shop) M.S/Cell 2020 से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए वर्ष 2020 में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें कुल 8 निविदादाताओं ने भाग लिया। इसमें से सागर मेडिकल हॉल को छोड़कर सभी निविदादाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया। हमने इतने दिनों के बाद इसकी वजह जाननी चाही तो पता चला कि इसके भी मुख्य खिलाड़ी डॉ० मनीष मंडल हैं। आईजीआईएमएस के मुख्य गेट पर सागर मेडिकल हॉल और सारण मेडिकल हॉल की दो दवा की दुकान थी, जिसे पोस्ट ऑफिस और सड़क चौड़ीकरण के कारण हटा दिया गया और आश्वासन दिया गया कि आपको परिसर में ही जगह दे दिया जायेगा। अधीक्षक मंडल ने बिना उचित प्रक्रिया के पालन के दोनों को परिसर में ही दुकान आवंटित कर दिया। सागर मेडिकल हॉल को ओ.पी.डी. के मुख्य सड़क पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के साथ दुकान आवंटित कर दिया गया और सारण मेडिकल हॉल को आईजीआईएमएस के पीछे दुकान आवंटित कर दिया गया। सागर मेडिकल

हॉल को 1+1 का ऑफर मिला, क्योंकि सागर मेडिकल हॉल के बटुये में दम था और उस दम पर डॉ० मनीष मंडल ने सागर मेडिकल हॉल को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (जेनेरिक दवा) के साथ ब्रान्डेड दवा दुकान खोलने की अनुमति दी। हमने माना कि आईजीआईएमएस स्वतंत्र इकाई है, लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी मिलता है और इसके गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं; तो इस पर भी BFR/GFR और CVC का नियम लागू होना चाहिए। निविदा निकाला गया प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिए लेकिन नियमों की अवहेलना कर सागर और सारण मेडिकल हॉल को दवा दुकान के लिए

Tender Notice No. : 01 / Tender (Shop) M.S. Cell / 2020

भारतीय जन औषधि परियोजना

INVITATION OF TENDER

FROM ELIGIBLE AND INTERESTED AGENCIES

FOR OPENING OF

"PRADHAN MANTRI BHARTIYA JAN AUSHADHI KENDRA"

(PMBJK)

at

IGIMS, SKEIKHPURA, PATNA - 800014

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)
Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org;
E-Mail: director@igims.org / ms@igims.org

Page 2 of 18

Office of the Director
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna (Bihar)

Tender Notice No:- 01/Tender (shop) M.S. Cell/2020

Sealed Tenders in two bid systems, Part-I Techno Commercial and Part II-Financial, are invited from Drugist/Chemist/Firms/Dealers/Companies for running medicine shop in IGIMS campus, Patna under Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra, Scheme near O.P.D of IGIMS.

Details of bidding document, term and conditions can be seen and downloaded from institute website www.igims.org.

12/2/2020
Prof. (Dr. N.R.Biswas)
Director
IGIMS, Patna.

Page 1 of 13

Office of the Director
INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
SHEIKHPURA, PATNA – 800 014 (Bihar, India)
Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org;
E-Mail: director@igims.org

NIT No.: 11/2015-16/Outsourcing/IGIMS/STORE
For Outsourcing of Computerise Service at IGIMS

Sealed Tender/Quotation is invited in Two Bid System (Technical and Price Bid)from reputed, competent and experienced Companies/Firms/Agencies for undertaking the computerized Registration work at OPD, Cash Collection work at the Cash Counter, Microbiology, Biochemistry, Hematology, Radiology, Pathology, All Wards, Matron Room, Clinician Rooms, & Emergency of the Institute on Outsourcing basis.

The tender documents will be available on Institute website. www.igims.org with effect from 29/08/2015. The pre-bid meeting will be held on 10/09/2015 at 11:00 AM in the conference hall of IGIMS Patna. The last date of submission of the completed bidding documents through registered/speed post/currier only is 21/09/2015 up to 4:00 PM. The date and time for opening of technical bid will be 22/09/2015 at 3:00 PM in the conference hall of IGIMS Patna. The details terms & conditions & scope of job may be seen and downloaded from Institute Website **www.igims.org**.

NIT No.:11/2015-16/Outsourcing/IGIMS/STORE

Sd/-
DIRECTOR
I.G.I.M.S. - Patna

आईजीआईएमएस परिसर में जगह आवंटित कर दिया गया। भारतीय जन औषधि केन्द्र के लिए निकाली गई निविदा में से एक निविदादाता बिहार मेडिकल ने जब इस पर हँगामा किया तो साम, दाम, दंड, भेद नीति के तहत उसका मुँह बंद करा दिया गया।

आईजीआईएमएस में सिक्युरिटी गार्ड/तकनीकी-गैर तकनीकी कर्मचारी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए डॉ० मनीष मंडल ने ट्रिंग डिटेक्टिव एण्ड सेक्युरिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड, साई एजेंसी, फ्रन्टलाईन सेक्युरिटी सर्विसेज और एस.आई.एस. सिक्युरिटी सर्विस इन चार कम्पनियों को विभिन्न निविदाओं के माध्यम से रखा है। इन कम्पनियों में डॉ० मनीष मंडल ने अपने तथा अपने आकाओं के लोगों को आरक्षण रोस्टर का पालन किये बिना, बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये रखवा दिया। डॉ० मनीष मंडल ने नौकरी रखवाने के नाम पर करोड़ों रूपये की उगाही की है, इसका पक्का सबूत केवल सच के पास मौजूद है। हम अपने अगले अंक में डॉ० मनीष मंडल के द्वारा असंवैधानिक रूप से रखे गए कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी का नाम आपको बतलायेंगे। यहाँ काम करने वाली ट्रिंग डिटेक्टिव एण्ड सेक्युरिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड जो महाराष्ट्र की कम्पनी है, उसने अपने कर्मचारियों को चार महीनें से वेतन नहीं दिया है। हिन्दु धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक होली में यहाँ काम करने वाले सिक्युरिटी गार्ड और गरीब कर्मचारियों के घर चूल्हा नहीं जला।

डॉ० मनीष मंडल

आईजीआईएमएस में भ्रष्टाचार का खेल

आईजीआईएमएस की दीवारें रोती, सत्ता के साए में बेबस होती।
फंड का खेल, घोटाले भारी, रिश्वतखोरों की लगी सवारी।
मनीष मंडल का ऊँचा नाम, पर अंदर फैला घोर अंधियारा।
कागजों में खेल, टेंडर का जाल, पैसा बंटा, पर काम बेहाल।
वेतन बंटा फर्जी दस्तखत पर, कहीं लगी बिल्डिंग, कहीं लगा डर।
लाखों की मशीनें धूत चाटती, बीमार जनता दर्द बाँटती।
फंड आया था इलाज के खातिर, पर निकला किसी जेब के अंदर।
मंत्री-मंडल सब मौन हैं बैठे, भ्रष्टाचार के गीत संग गाते।
पर जनता अब चुप न बैठेगी, हर चोरी की परतें खोलेगी।
न्याय का सूरज चमकेगा जब, हर घोटालेबाज फिर काँपेगा तब।

पूछने पर आईजीआईएमएस प्रशासन कहता है कि कम्पनी ने बिल ही नहीं दिया है। यह तो कमिशनखोरी या लालफितासाही का ही मामला हो सकता है। हमने कम्पनी के मालिक श्रीमती मनीषा जोशी के मोबाईल पर फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठाया, कम्पनी के बिहार इन्चार्ज सतीश सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही वेतन भुगतान कर देंगे। पता नहीं यह दिन कब आयेगा और आईजीआईएमएस प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा। हिन्दु धर्म की वकालत करने वाली भाजपा के मंत्री रहते हुए होली पर वेतन न मिलना मानवता को तार-तार करने वाली घटना है। मनीष मंडल का खौफ आईजीआईएमएस में नीचे से लेकर कर ऊपर तक के कर्मचारियों में देखा जा सकता है। मनीष मंडल को बिना दस वर्ष प्रशासनिक अनुभव के अधीक्षक बना दिया जाता है तो दूसरी तरफ मनीष मंडल की बात न मानने वाले आईजीआईएमएस के प्रिंसिपल रंजीत गुहा को हटाने की तैयारी कर ली गई है।

माननीय अनील कुमार शर्मा, सदस्य बिहार विधान परिषद ने बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से मनीष मंडल पर गंभीर सवाल किये थे कि पिछले 10 वर्षों से डॉ० मनीष मंडल इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में अधीक्षक (एम.एस.) के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ गेस्ट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, आचार समिति के सदस्य सचिव एवं सोटो (स्टेट आर्गेन एंड टिशू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन) के चेयरमैन पर पर बने हुए हैं।

...र विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

209वां सत्र

माननीय सभापति महोदय,

पिछले 10 वर्षों से डॉ. मनीष मंडल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में अधीक्षक (एम.एस.) के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ गेस्ट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, आचार समिति के सदस्य सचिव एवं सोटो (स्टेट आर्गेन एंड टिशू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन) के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। कई वरिष्ठ डॉक्टर को अनदेखी कर मंडल अधीक्षक बने हुए हैं। डॉ. मनीष मंडल द्वारा दायित्व की अनदेखी किए जाने के कारण वर्षों से लीवर ट्रांसप्लांट की मशीनें बर्बाद हो रही है। वर्षों से एक भी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है।

डॉ. मनीष मंडल के आई.जी.आइ.एम.एस. के अस्पताल अधीक्षक रहते हुए कई वित्तीय अनियमितता की गई है, सी.ए.जी. (महालेखाकार) ने संस्थान को कई चेतावनी भी दी है। कोरोना काल के दौरान सरकार की राशि में हेराफेरी करने का भी आरोप है। आई.जी.आइ.एम.एस. के आंतरिक जांच में प्रमाणित है।

मनीष मंडल द्वारा वर्षों से अस्पताल सहायक एवं अन्य कर्मियों के मानदेय भुगतान में अनियमितता की जा रही है। सरकार से दी जाने वाली राशि के भुगतान में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा हेराफेरी इनके संरक्षण में किया जा रहा है। सेवा प्रदाता के माध्यम से की गई नियुक्तियों में भी एक ही जाति विशेष एवं परिवार के लोगों को नौकरी दी गई है। यह भी बड़े अनियमितता का प्रमाण है।

डॉ. मनीष मंडल के एम.एस. रहते हुए करोड़ों रुपये की गाड़ियां खरीद की गई। लेकिन आज तक कई गाड़ियों का निबंधन नहीं कराया गया। आज की तिथि में कई गाड़ियां कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच गई है। जो गरीब जनता एवं आयकरदाताओं के गाढ़ी कमाई का यह सीधे-सीधे दुरुपयोग प्रकरण है।

अतः लोकहित में इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
अनिल कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प.-188/2025-900(1) वि.प.। दिनांक:-21.03.2025

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-25.03.2025 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

जाँच प्रतिवेदन

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–21611–06598 दिनांक–18.02.2022 के द्वारा श्री सुनील कुमार चौधरी, ग्राम + पोस्ट +थाना–महनार, जिला–वैशाली द्वारा परिवाद अनन्य संख्या–999990107022220635 से संबंधित मामले के जाँच हेतु अधोहस्ताक्षरी को सहायक जाँच पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया एवं एक पक्ष के अंदर जाँच प्रतिवेदन विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को हस्तगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव–सह–द्वितीय अपील प्राधिकार (लोक शिकायत निवारण), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस आशय के साथ प्रेषित करने का निदेश दिया गया ताकि नामित सहायक जाँच पदाधिकारी के नाम का अनुमोदन किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त उक्त परिवाद की जाँच हेतु दिनांक–11/05/2022 को अपराह्न 03:00 बजे तिथि व समय निर्धारित की गयी जिसकी सूचना निदेशक, इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना को विभागीय पत्रांक–598(18) दिनांक–09/05/2022 को उपलब्ध करायी गयी। दिनांक–11/05/2022 को जाँच के क्रम में इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किये जाने के कारण वांछित कागजात/ संचिका/ नियमावली उपलब्ध कराने तथा जाँच की अगली तिथि दिनांक– 13/05/2022 अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित करने हेतु विभागीय पत्रांक–604(18) दिनांक– 11/05/2022 द्वारा इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना को सूचना उपलब्ध करायी गयी। जाँच के दौरान संस्थान द्वारा समर्पित कागजात तथा श्री अनिल कुमार चौधरी, वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा समर्पित बयान के आलोक में श्री चौधरी को साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध कराने के निदेशार्थ विभागीय पत्रांक–617(18) दिनांक–13/05/2022 द्वारा सूचित किया गया। उक्त पत्र के द्वारा श्री संजय कुमार, उप निदेशक–II, इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना को उपलब्ध कराते हुए परिवाद से संबंधित तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

(1) जाँच के क्रम में संस्थान द्वारा पत्रांक–2523 दिनांक–13.05.2022 द्वारा इस परिवाद से संबंधित उत्तर सामग्री समर्पित किया गया जो निम्नवत है :–

क्र० सं०	वांछित सूचना	संस्थान का उत्तर
अंतर्लीन से संबंधित :–		
i	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–172/आ0सं0 दिनांक–10.10.1991' के द्वारा इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना में एम्स, नई दिल्ली में प्रचलित सेवा सम्बंधी नियम को लागू किया गया है, अतएव एम्स, नई दिल्ली में अंतर्लीन संबंधी नियम की प्रति दी जाय।	एम्स, दिल्ली में अंतर्लीन संस्थान की आवश्यकता के अनुसार केन्द्र सरकार के अंतर्लीन नियम के आधार पर पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासी निकाय के अनुमोदन द्वारा की जाती है। एम्स, नई दिल्ली के आदेश की छायाप्रति संलग्न (अनुलग्नक–01)
ii	केन्द्र सरकार में अंतर्लीन का नियम की प्रति दी जाए।	वर्ष 2019 में लागू केन्द्र सरकार में अंतर्लीन का नियम की प्रति संलग्न। (अनुलग्नक–02)

गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना की संबंधित संचिका व प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि अंतर्लीन के मामले में केन्द्र सरकार के DOPT के नियमों का पालन इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा नहीं किया गया है। नियमानुसार अंतर्लीन की प्रक्रिया से पूर्व इस हेतु विज्ञापन निकाला जाना था और विज्ञापन उपरान्त विहित प्रक्रिया का पालन कर अंतर्लीन किया जाना था, किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी के मामले में इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा बिना विज्ञापन निकाले और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना सीधे अंतर्लीन करते हुए शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अंतर्लीन नियमानुसार समरूप पद पर ही होना चाहिए, अर्थात श्री अनिल कुमार चौधरी के अंतर्लीन के समय अपने मूल विभाग केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में लेखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में इनका अंतर्लीन इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में लेखा पदाधिकारी के पद पर ही होना था किन्तु संस्थान द्वारा उक्त नियमों का पालन न कर लेखा पदाधिकारी के उच्चतर प्रोन्नति के पद वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर अंतर्लीन किया गया जो नियमानुकूल नहीं है। केन्द्र सरकार के नियम अनुसार सिर्फ केन्द्रीय व राज्य कर्मी ही अंतर्लीन की पात्रता रखते है किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी अंतर्लीन के समय केन्द्रीय व राज्यकर्मी नही थे। इसमें भी इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा केन्द्र सरकार के अंतर्लीन नियम का पालन नहीं किया गया।

(iii) अंतर्लीन के सम्बंध में केन्द्र सरकार का नियम स्पष्ट है। नियमानुसार अंतर्लीन पूर्णतः नयी नियुक्ति मानी जायेगी और संस्थान में सेवा की गणना अंतर्लीन की तिथि से होगी किन्तु संस्थान द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया है।

(2) प्रोन्नति हेतु एम्स, नई दिल्ली की नियमावली स्पष्ट है। वित्त सलाहकार के पद पर प्रोन्नति हेतु वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर नियमित रूप से 5 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी के मामले में इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया गया और मात्र दो साल की सेवावधि में ही प्रोन्नति हेतु DPC की बैठक आयोजित की गयी जो स्थापित नियमों का उल्लंघन है। संचिका के अवलोकन व स्थलीय जाँच से स्पष्ट होता है कि प्रोन्नति हेतु आयोजित DPC की बैठक की कार्यवाही व फलाफल सीलबंद लिफाफे में बंद है। इस प्रकार, प्रोन्नति के मामले में भी इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा स्थापित नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना पर किसी नियामक का नियंत्रण नहीं है। जबकि यह राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था है और सरकारी नियमों का पालन इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना के लिए बाध्यकारी है। किन्तु जाँचोपरान्त पाया गया कि इन्दिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना द्वारा इस मामले में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया और स्वेच्छाचारिता व मनमानेपन का परिचय देते हुए श्री अनिल कुमार चौधरी को अंतर्लीन व प्रोन्नति में स्थापित नियमों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ दिया गया जो रद्द करने योग्य है। श्री अनिल कुमार चौधरी को अंतर्लीन करने व प्रोन्नति का अनुचित लाभ प्रदान किये जाने से सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है, जो वसूली करने योग्य है। इस प्रकार जाँचोपरान्त परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये है।

आनन्द प्रकाश
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

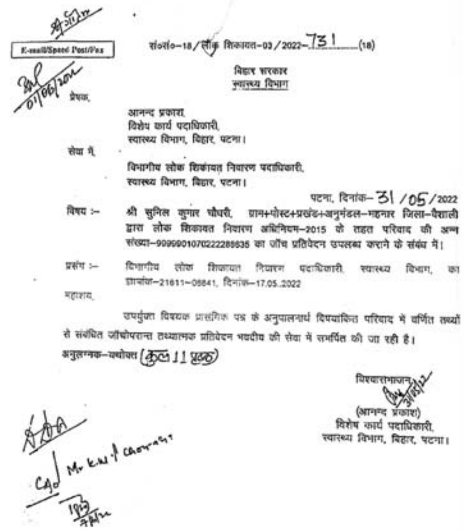

E-mail/Speed Post/Fax

सं०सं०-18/लोक शिकायत-03/2022-731 (18)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31/05/2022

विषय :- श्री सुनिल कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+प्रखंड+अनुमंडल-महनार जिला-वैशाली द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 के तहत परिवाद की अनन्य संख्या-9999901070222288535 का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, का ज्ञापांक-21611-08841, दिनांक-17.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालनार्थ विषयांकित परिवाद में वर्णित तथ्यों से संबंधित जाँचोपरान्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त (कुल 11 पृष्ठ)

विश्वासभाजन,
(आनन्द प्रकाश)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES: SHEIKHPURA: PATNA-14

कई वरिष्ठ डॉक्टर को अनदेखी कर मंडल अधीक्षक बने हुए हैं। डॉ० मनीष मंडल द्वारा दायित्व की अनदेखी किए जाने के कारण वर्षो से लीवर ट्रांसप्लांट की मशीनें बर्बाद हो रही हैं। वर्षों से एक भी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है।

डॉ० मनीष मंडल के इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के अधीक्षक रहते हुए कई वित्तीय अनियमितता की गई है, सी.ए.जी. (महालेखाकार) ने संस्थान को कई चेतावनी भी दी है। कोरोना काल के दौरान सरकार की राशि में हेराफेरी करने का भी आरोप है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के आंतरिक जाँच में प्रमाणित है।

मनीष मंडल द्वारा वर्षो से अस्पताल सहायक एवं अन्य कर्मियों के मानदेय भुगतान में अनियमितता की जा रही है। सरकार से ली जाने वाली राशि के भुगतान में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा हेराफेरी इनके संरक्षण में किया जा रहा है। सेवा प्रदाता के माध्यम से की गई नियुक्तियों में भी एक ही जाति विशेष एवं परिवार के लोगों को नौकरी दी गई है। यह भी बड़े अनियमितता का प्रमाण है। डॉ० मनीष मंडल के एम.एस. रहते हुए करोड़ों रूपये

विधान परिषद में उठा आईजीआईएमएस के अधीक्षक द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता व गलत तरीके से पद पर बने रहने का मुद्दा

■ ध्यानाकर्षण सूचना के तहत विधान पार्षद अनिल कुमार ने उठाया मुद्दा

आईजीआईएमएस अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

पटना | विधान परिषद में ध्यानाकर्षण के दौरान सदस्य अनिल कुमार ने आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अनिल कुमार ने कहा कि डॉ. मनीष मंडल द्वारा दायित्व की अनदेखी किए जाने के कारण वर्षों से लीवर ट्रांसप्लांट की मशीनें बर्बाद हो रही है। वर्षों से एक भी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। उनपर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि डॉ. मनीष मंडल अच्छे व्यक्ति है। सभी की मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सदन में चर्चा ठीक नहीं है।

अब चाय की प्याली में घुल मीठी होंगी कड़वी बातें

विधान परिषद तक पहुंची आईजीआइएमएस में वित्तीय अनियमितता और हेराफेरी की शिकायत

की गाड़ियों की खरीद की गई, लेकिन आज तक कई गाड़ियों का निबंध न नहीं कराया गया। आज की तिथि में कई गाड़ियां कबाड़ होने की स्थिति में पहुँच गई है। जो गरीब जनता एवं आयकरदाताओं के गाढ़ी कमाई का यह सीध े-सीधे दुरूपयोग प्रकरण है।

माननीय विधान पार्षद के इस प्रश्न से स्वास्थ्य विभाग सखते में आ गया और माननीय मंत्री स्वास्थ्य और माननीय सभापति बिहार विधान परिषद के दवाब में पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। राज्य सरकार ने बिहार में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार के सबसे बड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापन की, लेकिन राज्य की जनता का दुर्भाग्य यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और इस संस्थान का प्रमुख डॉ. राजेश कुमार को बना दिया गया। डॉ. राजेश कुमार सिंह अपने पार्टनर प्रवीण बहादुर के साथ मिलकर अपने मकान विशाल रेसिडेंसी में कैंसर की दवा का दुकान खोल लिया और कैंसर की दवा का मार्केटिंग करने लगा, उस दवा का एम.आर.पी. कई ब्रान्डेड दवाईयों से कई गुणा ज्यादे रखा गया था। उस समय के औषधि निरीक्षक ने जब विशाल रेसिडेंसी में रेड किया तो डॉ. राजेश कुमार का काला चिट्ठा खुल गया और उन्हें दुकान बंद करने पड़ी, लेकिन उनकी पहुँच का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस औषधि निरीक्षक को एक पुराने केस में फंसाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया, साथ ही आईजीआईएमएस गेट के सामने सस्ती कैंसर की दवा बेचने वाले दुकानदार के यहाँ कई बार रेड करवा दिया गया। आज राज्य सरकार द्वारा कैंसर मरीजों को 1.50 लाख रूपये का दवा मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है, यह दवा राज्य कैंसर संस्थान द्वारा निर्धारित दस दुकानों से लिया जाता है, जिसमें रामा मेडिकल हॉल, राधा कृष्णा मेडिकल हॉल, ऋषि

मंगल पांडेय

डॉ० राजेश कुमार सिंह

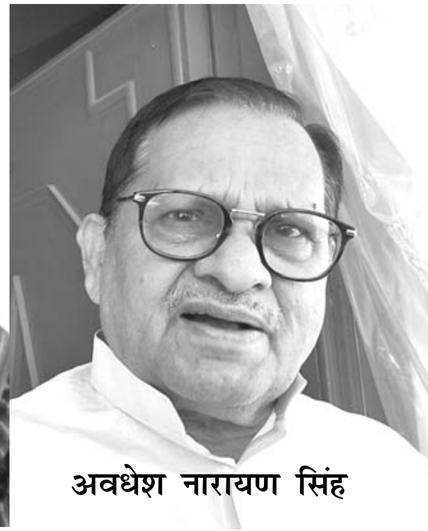
अवधेश नारायण सिंह

औषधि, पूजा मेडिकल हॉल, लाईफ केयर फार्मा प्रमुख है। इन दुकानों में Airmed Biotech, Jenovix Pharmaceuticals जैसे कम्पनियों की दवा ज्यादा मिलती है, क्योंकि कम्पनियों के प्रतिनिधि डॉक्टर के चैंबर में बैठे रहते हैं और डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का नीयत कमिशन फिक्स होता है। इन दुकानों में मिलने वाली दवा की कीमत की तुलना जब आप BMSICL और Tata Cancer Institute में मिलने वाली दवाओं से करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि कैंसर जैसी घातक बीमारी में डॉ० राजेश कुमार सिंह करोड़ों रूपये कमिशन के रूप में कैसे वसूलते हैं। उस समय के औषधि निरीक्षक ने व्यथित मन से कैंसर की दवाओं के लूट पर एक किताब "Cry of Cancer" लिखा, जिसमें बताया गया कि कैंसर की दवाओं में कई गुणा एम.आर.पी. रखा कर गरीब जनता को कैसे लूटा जा रहा है। हम उस औषधि निरीक्षक के नाम का खुलासा इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह अभी पटना से दूर गुमनामी का जिंदगी जी रहा है और कैंसर दवाओं के माफियाओं से उनके जान और नौकरी को भी खतरा है। यह घटना वर्ष 2015 की है, तब से लेकर आज तक डॉ० राजेश कुमार सिंह का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है और राज्य सरकार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पायी है।

आईजीआईएमएस में एक से लेकर एक भ्रष्टाचारी ने अवतार लिया है, उसमें से एक नाम है श्री परवेज अहमद खान। इनमें इतना अद्‌भुत ज्ञान है कि इनको सेवा काल में तीन बार एक्सटेंशन दिया गया और चौथी बार उनको सेवा अनुबंध पर रखा गया है। इन साहब की खासियत यह कि इनको आईजीआईएमएस में जन-सम्पर्क अधिकारी के अलावा गार्डेनिंग और सेनिटेशन का काम भी दे दिया गया है, जिससे वे दस से पंद्रह हजार का नकदी इसी पर निकाल कर उन पैसों से अपने आकाओं के नाजायज जरूरतों को पूरा करते हैं।

एक और अवतारी पुरूष का नाम है श्री उमा शंकर सिंह, जो कि आईजीआईएमएस में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हैं, जिनको सेवा-निवृति के बाद अगले दो वर्षो के लिए अनुबंध अवधि विस्तार दिया गया है। इनकी विशेषता है कि ये डॉक्टरों के नीजी अस्पतालों में मरीज भेजते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों के ओ.पी.डी. चैम्बरों में ज्यादा मरीज भेजते हैं, ताकि उस में से कुछ मरीज उन डॉक्टरों के नीजी अस्पतालों में पहुँच जाये। आईजीआईएमएस शाम के बाद मरीजों की भर्ती नहीं लेता है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ० मनीष मंडल की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। भारत में एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री ने जन्म लिया। विदेश में

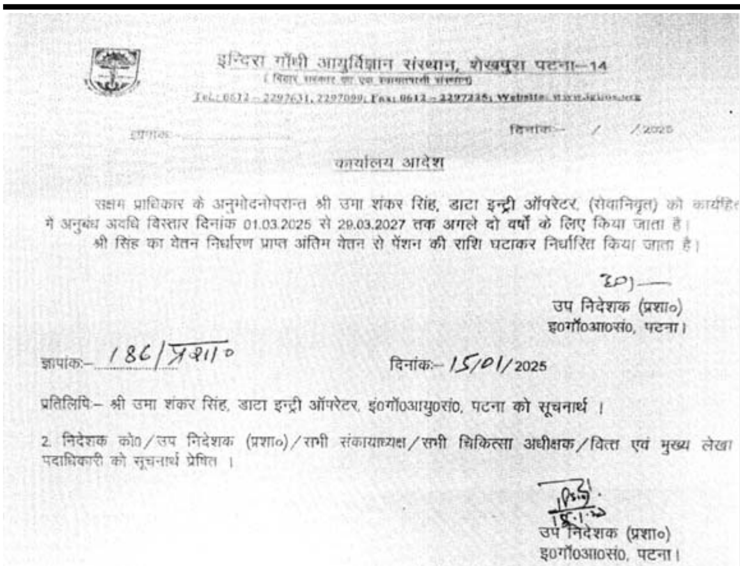
इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

ज्ञापांक-   दिनांक- / /2025

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री उमा शंकर सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, (सेवानिवृत) को कार्यहित में अनुबंध अवधि विस्तार दिनांक 01.03.2025 से 29.03.2027 तक अगले दो वर्षों के लिए किया जाता है।

श्री सिंह का वेतन निर्धारण प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटाकर निर्धारित किया जाता है।

उप निदेशक (प्रशा०)
इ०गाँ०आ०सं०, पटना।

ज्ञापांक- 186/प्रशा०   दिनांक- 15/01/2025

प्रतिलिपि- श्री उमा शंकर सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, इं०गाँ०आयु०सं०, पटना को सूचनार्थ।

2. निदेशक को०/उप निदेशक (प्रशा०)/सभी संकायाध्यक्ष/सभी चिकित्सा अधीक्षक/वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक (प्रशा०)
इ०गाँ०आ०सं०, पटना।

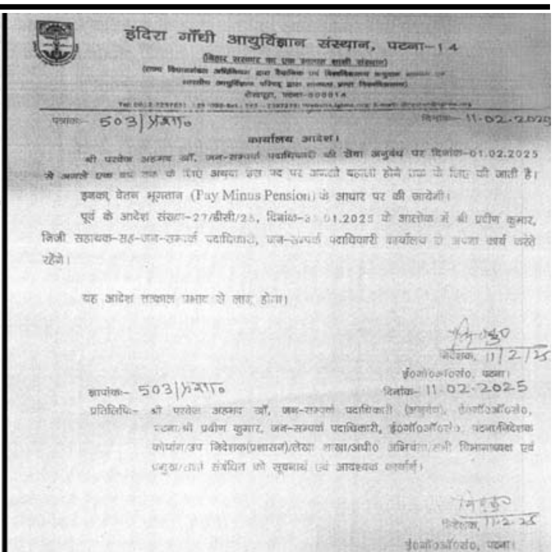
इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना-14

पत्रांक- 503/प्रशा०   दिनांक- 11.02.2025

कार्यालय आदेश।

श्री परवेज अहमद खाँ, जन-सम्पर्क पदाधिकारी की सेवा अनुबंध पर दिनांक-01.02.2025 से अगले एक वर्ष [illegible] के लिए अथवा इस पद पर [illegible] होने तक के लिए दी जाती है।

इनका वेतन भुगतान (Pay Minus Pension) के आधार पर की जायेगी।

पूर्व के आदेश संख्या-27/डीसी/25, दिनांक-[illegible].01.2025 के आलोक में श्री प्रवीण कुमार, निजी सहायक-सह-जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जन-सम्पर्क पदाधिकारी कार्यालय [illegible] कार्य करते रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

निदेशक, 11/2/25
इं०गाँ०आ०सं०, पटना।

ज्ञापांक- 503/प्रशा०   दिनांक- 11.02.2025

प्रतिलिपि- श्री परवेज अहमद खाँ, जन-सम्पर्क पदाधिकारी (अनुबंध), इं०गाँ०आ०सं०, पटना/श्री प्रवीण कुमार, जन-सम्पर्क पदाधिकारी, इं०गाँ०आ०सं०, पटना/निदेशक कोषांग/उप निदेशक(प्रशासन)/लेखा शाखा/अधी० अभियंता/सभी विभागाध्यक्ष एवं [illegible] संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

निदेशक, 11.2.25
इं०गाँ०आ०सं०, पटना।

देश के खिलाफ बोलने वाले अर्थशास्त्री अम्रत्य सेन को नोबल प्राईज से नवाजा गया। उस महान अर्थशास्त्री की सोच तो पश्चिमी देशों की थी, लेकिन भारत के अर्थतंत्र के खिलाफ बोलने के लिए उसे नोबल प्राईज से सम्मानित किया गया और दूसरे हमारे बिहार के अनील कुमार चौधरी हैं, जिनके महान ज्ञान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 172-आ०सं०, दिनांक 10/01/1991 के द्वारा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में एम्स, नई दिल्ली में प्रचलित सेवा संबंधी नियम लागू करवाने को धत्ता बताते हुए श्री अनील कुमार चौधरी को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा में लेखा पदाधिकारी से आईजीआईएमएस में वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त (नियमित) कर दिया गया। अम्रत्य सेन को भारत विरोधी अर्थ ज्ञान देने के लिए नोबल प्राईज दिया गया तो दूसरी तरफ अनील कुमार चौधरी को भ्रष्टाचार का नियमितीकरण या यूं कहें कानूनी जामा पहनाने के लिए आईजीआईएमएस में वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी बनाया गया। इतना ही नहीं उनको भ्रष्टाचार की रकम आकाओं तक नियमित रूप से पहुँचाने के कारण मात्र दो वर्षों में DPC की बैठक कर वित्त सलाहकार के पद पर भी सुशोभित कर दिया गया।

अनील कुमार चौधरी जैसे महान विभूति के नियुक्ति प्रक्रिया को जानने के लिए आनंद प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को विभागीय लोक शिकायत पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग ने जाँच का आदेश दिया। जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि:-

☞ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-172/आ०सं०, दिनांक-10/10/1991 के अनुसार इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में एम्स, नई दिल्ली में प्रचलित सेवा संबंधी नियम लागू है, किन्तु अंतर्लीन करने के संबंध में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा एम्स, नई दिल्ली का संबंधित नियम की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। एम्स, नई दिल्ली के वेबसाईट में भी संबंधित नियम की प्रति उपलब्ध नहीं है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन में बताया गया है कि अंतर्लीन के मामले में केन्द्र सरकार के DOPT के नियम का अनुपालन किया गया है।

☞ केन्द्र सरकार के DOPT द्वारा अंतर्लीन संबंधी नियम का अवलोकन किया गया जो Swamy's book of establishment and administration में उल्लेखित है। साथ ही, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की संबंधित संचिका व प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि अंतर्लीन के मामले में केन्द्र सरकार के DOPT के नियमों का पालन इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा नहीं किया गया है। नियमानुसार अंतर्लीन की प्रक्रिया से पूर्व इस हेतु विज्ञापन निकाला जाना था और विज्ञापन उपरान्त विहित प्रक्रिया का पालन कर अंतर्लीन किया जाना था, किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी के मामले में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा बिना विज्ञापन निकाले और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना सीधे अंतर्लीन करते हुए शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अंतर्लीन नियमानुसार समरूप पद पर ही होना चाहिए, अर्थात श्री अनिल कुमार चौधरी के अंतर्लीन के समय अपने मूल विभाग केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में लेखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में इनका अंतर्लीन इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में लेखा पदाधिकारी के पद पर ही होना था किन्तु संस्थान द्वारा उक्त नियमों का पालन न कर लेखा पदाधिकारी के उच्चतर प्रोन्नति के पद वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर अंतर्लीन किया गया जो नियमानुकूल नहीं है। केन्द्र सरकार के नियम अनुसार सिर्फ केन्द्रीय व राज्य कर्मी ही अंतर्लीन की पात्रता रखते हैं किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी अंतर्लीन के समय केन्द्रीय व राज्यकर्मी नहीं थें। इसमें भी इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा केन्द्र सरकार के अंतर्लीन नियम का पालन नहीं किया गया।

☞ अंतर्लीन के सम्बंध में केन्द्र सरकार का नियम स्वतः स्पष्ट है। नियमानुसार अंतर्लीन पूर्णतः नयी नियुक्ति मानी जायेगी और संस्थान में सेवा की गणना अंतर्लीन की तिथि से होगी किन्तु संस्थान द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया है।

(2) प्रोन्नति हेतु एम्स, नई दिल्ली की नियमावली स्पष्ट है। वित्त सलाहकार के पद पर प्रोन्नति हेतु वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर नियमित रूप से 5 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। किन्तु श्री अनिल कुमार चौधरी के मामले में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया गया और मात्र दो साल की सेवावधि में ही प्रोन्नति हेतु DPC की बैठक आयोजित की गयी जो स्थापित नियमों का उल्लंघन है। संचिका के अवलोकन व स्थलीय जाँच से स्पष्ट होता है कि प्रोन्नति हेतु आयोजित DPC की बैठक की कार्यवाही व फलाफल सीलबंद लिफाफे में बंद है। इस प्रकार, प्रोन्नति के मामले में भी इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा स्थापित नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना पर किसी नियामक का नियंत्रण नहीं है। जबकि यह राज्य सरकार के अधीन स्वायत संस्था है और सरकारी नियमों का पालन इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए बाध्यकारी है। किन्तु जाँचोपरान्त पाया गया कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा इस मामलें में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया और स्वेच्छाचारिता व मनमानेपन का परिचय देते हुए श्री अनिल कुमार चौधरी को अंतर्लीन व प्रोन्नति में स्थापित नियमों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ दिया गया जो रद्द करने योग्य है। श्री अनिल कुमार चौधरी को अंतर्लीन करने व प्रोन्नति का अनुचित लाभ प्रदान किये जाने से सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है, जो वसूली करने योग्य है। इस प्रकार जाँचोंपरान्त परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये है।

इस संबंध में माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा श्री मुकेश कुमार यादव ने प्रश्न पूछा कि आईजीआईएमएस प्रशासन द्वारा वर्ष 2019 में नियुक्त श्री अनील कुमार चौधरी, मुख्य लेखा पदाधिकारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी के द्वारा वर्ष 2022 में की गई जाँच में इनकी नियुक्ति अवैध पाये जाने के बाद भी अबतक स्वास्थ्य विभाग एवं इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि हाँ तो सरकार इन दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है। नहीं तो क्यों? सरकार ने इस पर अपना जवाब दिया कि नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जा रही है। यह प्रश्न बिहार विधान सभा में 16/02/2022 को पूछा गया था, लेकिन आज तक अनील कुमार चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो बिहार विधान सभा के अवमानना का मामला है। अनील कुमार चौधरी पर कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि अनील चौधरी को डॉ० मनीष मंडल का बर्धस्थ प्राप्त है।●

बिहार पर्यटन निगम में भ्रष्टाचार का जाल

कब होगी सख्त कार्रवाई?

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

पर्यटन निगम का मुख्य उद्देश्य बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों व सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए कार्य करना है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSTDC) में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और पदाधिकारियों की मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्राप्त दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि निगम में व्यापक पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियाँ और नियमों की अनदेखी हो रही है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निगम में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से कई घोटाले सामने आए हैं। बिहार पर्यटन निगम का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने इसकी छवि धूमिल कर दी है। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार इसी तरह जारी रहा, तो इसका सीधा नुकसान राज्य के पर्यटन उद्योग को होगा। विभिन्न संगठनों और नागरिक समूहों ने इस मामले में सीबीआई या विजिलेंस विभाग से जाँच कराने की माँग की है, ताकि इस घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इनमें से कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं :-

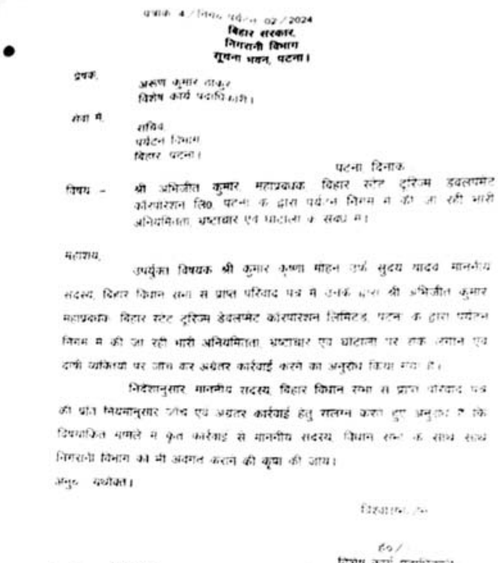
पत्रांक 4/निग० पर्यटन 02/2024
बिहार सरकार,
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,
अरुण कुमार ठाकुर
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,
सचिव
पर्यटन विभाग
बिहार पटना।

पटना दिनांक

विषय - श्री अभिजीत कुमार, महाप्रबंधक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के द्वारा पर्यटन निगम में की जा रही भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं घोटाला के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री कुमार कृष्णा मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद पत्र में उनके द्वारा श्री अभिजीत कुमार महाप्रबंधक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के द्वारा पर्यटन निगम में की जा रही भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं घोटाला पर रोक लगाने एवं दोषी व्यक्तियों पर जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

निदेशानुसार माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति नियमानुसार जाँच एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित मामले में कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य, विधान सभा के साथ साथ निगरानी विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 3457 /पटना दिनांक 18/07/24

प्रतिलिपि- श्री कुमार कृष्णा मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा आवास-358/400, तल सं0-05, राजधानी नगर, पटना बिहार को उनके परिवाद पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

18.07.24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

☞ **होटल कौटिल्य बिहार मरम्मत घोटाला :-** BSTDC के अंतर्गत होटल कौटिल्य बिहार का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रारंभ में 90 लाख रूपये की निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इस बजट को बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये तक कर दिया गया। इस वृद्धि में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हुई, जिसमें कागजों पर ही फर्जी काम दिखाकर धन निकासी की गई।

☞ **वित्तीय नियमों की अनदेखी :-** बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के तहत कोई भी निर्माण कार्य तीन वर्षों तक पुन: नहीं किया जा सकता है, लेकिन BSTDC में इस नियम की खुलेआम अवहेलना हो रही है। कई परियोजनाओं में बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नए कार्य स्वीकृत कर दिए गए।

☞ **सरकारी संपत्तियों की नीलामी में**

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933,2675935 Fax: 0612-2675934

पत्रांक........ दिनांक ....

प्रेषक,
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

Registered Post & E-Mail

सेवा में,

M/s S.R. Construction.
Shashi Place, Ram Krishna Nagar
Ward No-20, Begusaria- Bihar-851101

C. Program
Ali
03/10/23

विषयः **Construction of Plug and play Pre- Engineered Multi Story Building at Industrial Area Begusarai, Phase II कार्य हेतु Debar करने के संबंध में।**

प्रसंगः इस कार्यालय का पत्रांक– 4677/Tech. दिनांक– 25.08.2023 एवं प्राधिकार के पत्रांक 5104/Tech दिनांक 15.09.23

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे कहना है कि Construction of Plug and play Pre-Engineered Multi Story Building at Industrial Area Begusarai, Phase II का एकरारनामा सं0 52/SBD/2022-23 दिनांक 24.12.2022 किया गया है, जिसके अनुसार कार्य प्रांरभ करने की तिथि दिनांक 10.12.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.03.2023 थी। उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अवधि वर्त्तमान में समाप्त हो चुकी है। परंतु अबतक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है।

उक्त के संदर्भ में प्राधिकार के पत्रांक 4677/Tech दिनांक 25.08.23 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में आपके पत्रांक 00 दिनांक 20.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आये है:–

कार्य समाप्ति अवधि के 06 माह बीत जाने के बाद भी अबतक लगभग 24 % कार्य ही पूर्ण किया गया है। प्राधिकार के पत्रांक 4677/Tech दिनांक 25.08.23 में उल्लेखित प्रासंगिक पत्रों एवं Site Order Book के माध्यम संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परंतु संवेदक द्वारा कार्य में अपेक्षित नहीं लाया गया। पुनः पत्रांक 4115/Tech दिनांक 21.07.2023 उक्त कार्य में गति लाने हेतु नोटिस भी दिया गया, परंतु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है। Drawings चरणबद्ध आपको उपलब्ध कराया जाता रहा है। उक्त परियोजना एकरारनामा के अनुसार अत्यंत मंद गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि किसी परिस्थिति में प्रासंगिक योजना को प्रावधानित समय–सीमा में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

अतः **M/s S.R. Construction** द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके **निबंधन संख्या– IDA/31/Class-1/2022** को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक 5448/Tech दिनांक 30/09/23
प्रतिलिपिः जन–संपर्क पदाधिकारी, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

पत्रांक–4/निग०पर्यटन–03/2023..........

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

निबंधित ई–मेल

प्रेषक,
मो० जहाँगीर आलम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,
श्री शंभू प्रसाद यादव,
पिता–श्री सीताराम राय,
वार्ड–06, जितवारपुर निजामत,
समस्तीपुर, बिहार, पिन–848134
<shambhuprasadyadav2016@gmail.com>

पटना, दिनांक..........

विषय : श्री अमरेन्द्र अजय, कनीय अभियंता (संविदा) श्री राकेश रोशन, सहायक प्रबंधक, लेखा एवं श्री कमलेश शर्मा, सहायक अभियंता (संविदा) के विरूद्ध परिवाद।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि आपके नाम से भेजा गया उपर्युक्त विषयक परिवाद–पत्र निगरानी विभाग में प्राप्त हुआ है। पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आपसे निम्नांकित कार्रवाई/सूचना अपेक्षित है:–

(क) इस बात की सम्पुष्टि की जाय कि विषयांकित परिवाद–पत्र पर आपका हस्ताक्षर है एवं आपको तथ्यों की पूरी जानकारी है।

(ख) न्यायालय का शपथ–पत्र **(मूल रूप में)** संलग्न करें कि आपको तथ्यों की पूरी–पूरी जानकारी है और उसे प्रमाणित करने के लिए आप निगरानी विभाग को सहयोग करने को तैयार हैं।

(ग) यदि आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य आपके पास हो तो उसकी छाया प्रति निगरानी विभाग को उपलब्ध करायें।

उपर्युक्त कार्रवाई के पश्चात् यदि आपसे निर्धारित अवधि के अन्दर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो समझा जायेगा कि आपने परिवाद–पत्र नहीं दिया है एवं यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 1401 **/पटना, दिनांक :** 16/3/2023
प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव। 16/3

भ्रष्टाचार :– निगम के पुराने होटलों और संपत्तियों की नीलामी में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। नियमानुसार नीलामी पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने मिलीभगत कर औने–पौने दामों पर संपत्तियों को बेच दिया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ।

☞ **संविदा पर रखे गए अभियंताओं की मनमानी :**– पर्यटन निगम में एक संविदा कनिय अभियंता को मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत दिखाया गया है, जबकि उसके पास न तो आवश्यक योग्यता है और न ही कोई वैध पदनाम। यह अभियंता योजनाओं की स्वीकृति से लेकर बजट आवंटन तक में हस्तक्षेप करता है और ठेकेदारों से कमीशन की माँग करता है।

☞ **अधिकारियों की सांठ-गांठ से सरकारी धन की लूट :**– बिहार पर्यटन निगम में कुछ अधिकारी लगातार सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल पाए गए हैं। विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई राशियों की जाँच करने पर कई मामलों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें योजनाओं की संचिकाएँ भी गायब कर दी गईं।

☞ **दोहरे सेवा नियमों का उल्लंघन :**– BSTDC के कई कर्मचारी अन्य विभागों में सेवा कर रहे हैं, जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियमानुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी दो पदों पर एक साथ कार्य नहीं कर सकता, लेकिन निगम में कुछ कर्मचारियों को दोहरी सेवा में रखा गया है।

☞ **अधिकारियों को बचाने के प्रयास :**– भ्रष्टाचार की शिकायतों के बावजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतों को दबाने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

BSTDC के सहायक लेखा प्रबंधक राकेश रोशन के खिलाफ भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक ठेकेदार द्वारा दायर शपथ पत्र में बताया गया कि उनसे गैरकानूनी तरीके से पैसे माँगे गए। रिश्वत न देने के कारण उन्हें पिछले चार वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार बिना किसी ठोस कारण के भुगतान में देरी की गई, अनुबंध के अनुसार किए गए कार्यों के बावजूद अनावश्यक आपत्तियाँ लगाई गईं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर अनुचित रूप से ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। इन मामलों को लेकर अब कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की माँग की गई है। कई ठेकेदारों और प्रभावित व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में भी अपील दायर करने की योजना बनाई है। इन सभी घोटालों और अनियमितताओं के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं और बिना किसी डर के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार का यह चक्र चलता रहेगा। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी,

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञा०सं०-भवन-03/स्था०विविध-01/2025 1153(7) /पटना दिनांक- 31/1/25

-:: आदेश ::-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी०(सी०) संख्या-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-19 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 294 (दो सौ चौरानवें) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-07 एवं समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम/स्थायी पता	पंजीयन सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित सर्वेकित सीरियल नंबर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि/अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1	SHAILENDRA KUMAR SINHA/PATNA	BINDESHWARI PRASAD/ BAHADURPUR HOUSING COLONY BIHAR, PATNA	BR001500 10088666	3	23-04-1966	BC/ 60-UR	
2	OM PRAKASH RAM/ GARHWA	NAGENDRA RAM/ CHAPRI, JHARKHAND/ GARHWA BHAWNATHPUR	BR001500 10062666	21	12-01-1987	GENERAL/ 60-UR	
3	CHANDAN KUMAR/ NALANDA, BIHAR	RAMDEV PRASAD/ BARI PAHARI, SOH SARAI, NALANDA, BIHAR	BR001500 10045837	71	08-04-1992	BC/ 60-UR	
4	RAKESH KUMAR PODDAR/ BHAGALPUR	SURESH PODDAR/ FATEHPUR, KHANOKHAR, BIHAR, NALANDA	BR001500 10063656	85	18-08-1986	BC/ 60-UR	
5	GOBIND KUMAR SHARMA/ BIHAR	ARBIND KUMAR SHARMA/PURANA BHOJPUR, BIHAR, BUXAR, DUMRAON	BR001500 10065365	126	13-10-1987	GENERAL/ 60-UR	
6	AMRENDRA AJAY/ BIHAR	RAM SWARUP SINGH/ LAKHISARAI, BIHAR	BR001500 10021625	165	21-12-1979	GENERAL/ 60-UR	
7	NEERAJ KUMAR/ BIHAR	AWADHESH KUMAR/ KHEDRU BIGHA, ANANDPUR, BIHAR, ARWAL	BR001500 10019954	168	05-06-1991	EBC/ 60-UR	
8	SUDHIR KUMAR SINGH/ BHOJPUR	RAMANUGRAH SINGH/GOPALPUR, KHANGAON, BIHAR, BHOJPUR, KOILWAR, CHANDI	BR001500 10054345	210	26-06-1992	BC/ 60-UR	
9	RAJESH KUMAR/BHAGALPUR	VBRAHEMDEV SINGH/ BUDHCHAK, BIHAR, BHAGALPUR	BR001500 10068294	225	16-08-1988	ST/ 60-UR	

ज्ञापांक-भवन-03/स्था०विविध-01/2025 ________/पटना, दिनांक-________

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भवन-03/स्था०विविध-01/2025 ________/पटना, दिनांक-________

प्रतिलिपि :-सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भवन-03/स्था०विविध-01/2025 1153(7) /पटना, दिनांक- 31/1/25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अवर सचिव/प्रभारी बजट प्रशाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) दिनांक-11.02.2025 तक अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव।

या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? यदि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया गया, तो इससे न केवल पर्यटन निगम की साख प्रभावित होगी, बल्कि बिहार के विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

☞ **बिहार पर्यटन निगम में भ्रष्टाचार का गहरा जाल, टेंडर घोटाले की उठी मांग** :- बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSTDC) में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि निगम में वर्षों से एक संगठित माफिया गिरोह सक्रिय है, जो नियमों को ताक पर रखकर टेंडर की बिक्री और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहा है। मुख्य अभियंता अशोक कुमार और कनिष्ठ अभियंता (संविदा) अमरेंद्र अजय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि अमरेंद्र अजय ने निगम के भीतर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और निविदा प्रक्रिया को मनमाने तरीके से संचालित कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ फर्मों को गलत तरीके से टेंडर आवंटित किए गए, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि अमरेंद्र अजय के खिलाफ दो सरकारी विभागों में एक साथ नौकरी करने का भी मामला सामने आया है। दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने भवन निर्माण विभाग में नियमित नियुक्ति मिलने के बावजूद बिहार पर्यटन निगम में अपने पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं कराया और समानांतर रूप से दोनों जगह कार्यरत है।

पत्रांक 871 /गोपनीय

विशेष निगरानी इकाई
निगरानी विभाग
05, दरोगा प्रसाद राय पथ,
बिहार, पटना ।
दूरभाष:-0612-2506253

प्रेषक,
पुलिस उपाधीक्षक,
विशेष निगरानी इकाई,
बिहार, पटना।

सेवा में,
दीपू पासवान,
पिता-आदित्य पासवान,
सा0-वार्ड न0-04 कृष्णाब्रह्म, पो0-टुडीगंज,
नेनुआन, जिला-बक्सर, पिन-802111

पटना, दिनांक-2/11/2024

विषय:- दिनांक-12.11.2024 को 10:00 बजे पूर्वा0 में उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच एवं कार्रवाई हेतु आपसे कुछ बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु आप दिनांक-12.11.2024 को समय-10:00 बजे पूर्वा0 में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के कार्यालय में सदेह उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

कृपया इसे अति-आवश्यक समझें।

(श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो)
पुलिस उपाधीक्षक,
विशेष निगरानी इकाई,
बिहार, पटना।

इस मामले में सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। विपक्षी दलों के कुछ विधायकों ने भी इस घोटाले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह जांच के दायरे में रहकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और बिहार में सुशासन की परिकल्पना को कितना साकार कर पाते हैं।

☞ **कानूनी नोटिस : अर्जुन मिश्रा द्वारा गंभीर आरोपों के**

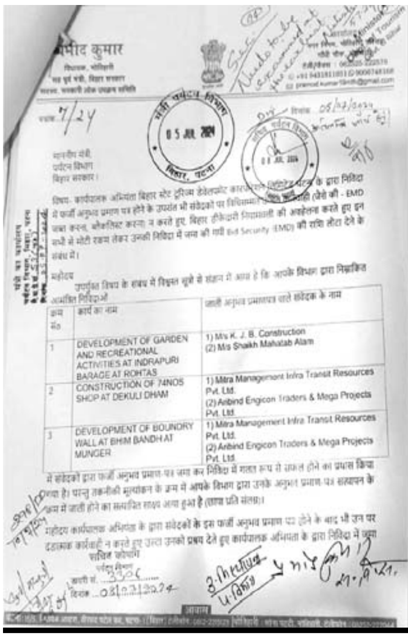

प्रमोद कुमार

पत्रांक 7/24

दिनांक 05/07/2024

माननीय मंत्री,
पर्यटन विभाग
बिहार सरकार।

महोदय

क्रम सं०	कार्य का नाम	जाली अनुभव प्रमाणपत्र वाले संवेदक के नाम
1	DEVELOPMENT OF GARDEN AND RECREATIONAL ACTIVITIES AT INDRAPURI BARAGE AT ROHTAS	1) M/s K. J. B. Construction (2) M/s Shaikh Mahatab Alam
2	CONSTRUCTION OF 74NOS SHOP AT DEKULI DHAM	1) Mitra Management Infra Transit Resources Pvt. Ltd. (2) Aribind Engicon Traders & Mega Projects Pvt. Ltd.
3	DEVELOPMENT OF BOUNDRY WALL AT BHIM BANDH AT MUNGER	1) Mitra Management Infra Transit Resources Pvt. Ltd. (2) Aribind Engicon Traders & Mega Projects Pvt. Ltd.

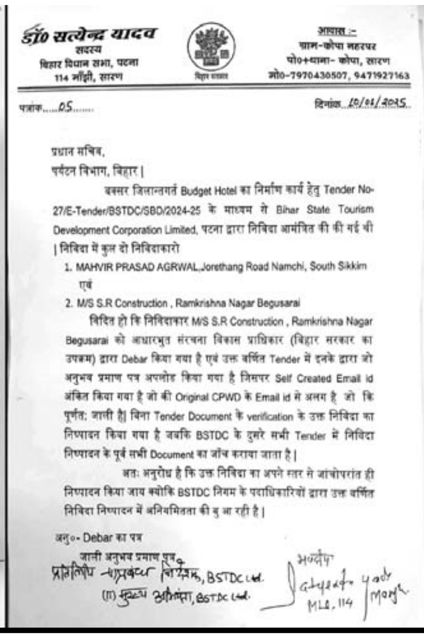

डॉ० सत्येन्द्र यादव
सदस्य
बिहार विधान सभा, पटना
114 माँझी, सारण

आवास :-
ग्राम-कोपा महरपर
पो०+थाना- कोपा, सारण
मो0-7970430507, 9471927163

पत्रांक 05

दिनांक 10/01/2025

प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार।

बक्सर जिलान्तगर्त Budget Hotel का निर्माण कार्य हेतु Tender No-27/E-Tender/BSTDC/SBD/2024-25 के माध्यम से Bihar State Tourism Development Corporation Limited, पटना द्वारा निविदा आमंत्रित की की गई थी। निविदा में कुल दो निविदाकारो

1. MAHVIR PRASAD AGRWAL,Jorethang Road Namchi, South Sikkim
एवं
2. M/S S.R Construction , Ramkrishna Nagar Begusarai

विदित हो कि निविदाकार M/S S.R Construction , Ramkrishna Nagar Begusarai को आधारभुत संरचना विकास प्राधिकार (बिहार सरकार का उपक्रम) द्वारा Debar किया गया है एवं उक्त वर्णित Tender में इनके द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है जिसपर Self Created Email id अंकित किया गया है जो की Original CPWD के Email id से अलग है जो कि पूर्णतः जाली है। बिना Tender Document के verification के उक्त निविदा का निष्पादन किया गया है जबकि BSTDC के दुसरे सभी Tender में निविदा निष्पादन के पूर्व सभी Document का जाँच कराया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निविदा का अपने स्तर से जांचोपरांत ही निष्पादन किया जाय क्योंकि BSTDC निगम के पदाधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित निविदा निष्पादन में अनियमितता की बु आ रही है।

अनु०- Debar का पत्र
जाली अनुभव प्रमाण पत्र

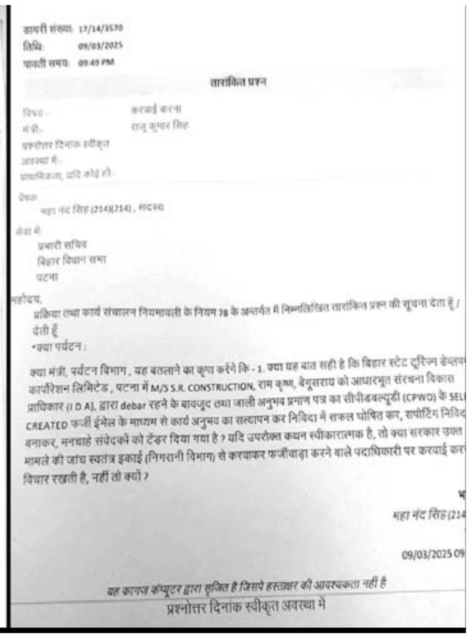

डायरी संख्या: 17/14/3570
तिथि: 09/03/2025
पावती समय: 09:49 PM

तारांकित प्रश्न

विषय:- करवाई करना
मंत्री:- राजू कुमार सिंह
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
महा नंद सिंह (214)(214) , सदस्य

सेवा में
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित तारांकित प्रश्न की सूचना देता हूं / देती हूँ
*क्या पर्यटन :

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग , यह बतलाने का कृपा करेंगे कि - 1. क्या यह बात सही है कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलप[...] कार्पोरेशन लिमिटेड , पटना में M/S S.R. CONSTRUCTION, राम कृष्ण, बेगूसराय को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (I D A), द्वारा debar रहने के बावजूद तथा जाली अनुभव प्रमाण पत्र का सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के SEL[...] CREATED फर्जी ईमेल के माध्यम से कार्य अनुभव का सत्यापन कर निविदा में सफल घोषित कर, सपोर्टिंग निविद[...] बनाकर, मनचाहे संवेदकों को टेंडर दिया गया है ? यदि उपरोक्त कथन स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच स्वतंत्र इकाई (निगरानी विभाग) से करवाकर फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी पर करवाई कर[...] विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

महा नंद सिंह (214

09/03/2025 09

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था मे

साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी :- एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में, अर्जुन मिश्रा ने बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSTDC) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने अपने अधिकारों के हनन और व्यक्तिगत क्षति का दावा किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला अर्जुन कुमार मिश्रा, पिता स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्रा के विरुद्ध पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर, गलत तथ्यों पर आधारित, गैर कानूनी कार्रवाई किए जाने, प्रताड़ित करने एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने से संबंधित है। अर्जुन मिश्रा के वकील द्वारा भेजे गए इस कानूनी नोटिस में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSTDC) से कानूनी और नैतिक दायित्वों को पूरा करने की मांग की गई है।

✯ **नोटिस में उल्लेखित मुख्य बिंदु :-**

☞ **आरोपों का विवरण :-** अर्जुन मिश्रा ने अपने नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके साथ विशिष्ट आरोप]किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति प्रभावित हुई है।

☞ **कानूनी धाराएं :-** नोटिस में भारतीय कानून की संबंधित धारा का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह कार्य गैर-कानूनी है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

☞ **मुआवजे की माँग :-** कानूनी नोटिस में अर्जुन मिश्रा ने राशि या अन्य मुआवजे की माँग की है ताकि उनकी हुई क्षति की भरपाई हो सके।

☞ **समय-सीमा :-** प्रतिवादी को निर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस का उत्तर देने या उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा मामले को न्यायालय में ले जाया जाएगा।

✯ **क्या कहते हैं विशेषज्ञ? :-** कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो यह मामला न्यायालय में जा सकता है, जिससे संबंधित पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में उचित समाधान के लिए दोनों पक्षों को कानूनी रूप से संतुलित निर्णय लेना चाहिए।

यदि प्रति-पक्ष इस नोटिस पर संतोषजनक उत्तर नहीं देता या कानूनी समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाता, तो अर्जुन मिश्रा न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इससे न केवल कानूनी जटिलताएँ बढ़ेंगी, बल्कि संबंधित पक्षों को कानूनी खर्च और समय की हानि भी झेलनी पड़ सकती है।

यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ सकता है और इससे संबंधित पक्षों को कानूनी तौर पर जवाबदेही तय करनी होगी। अब देखना यह होगा कि प्रति-पक्ष इस नोटिस का जवाब किस प्रकार देता है और आगे की कानूनी कार्रवाई कैसी होगी।●

कबाड़ डॉक्टर का कब्रगाह है राज्य स्वास्थ्य समिति

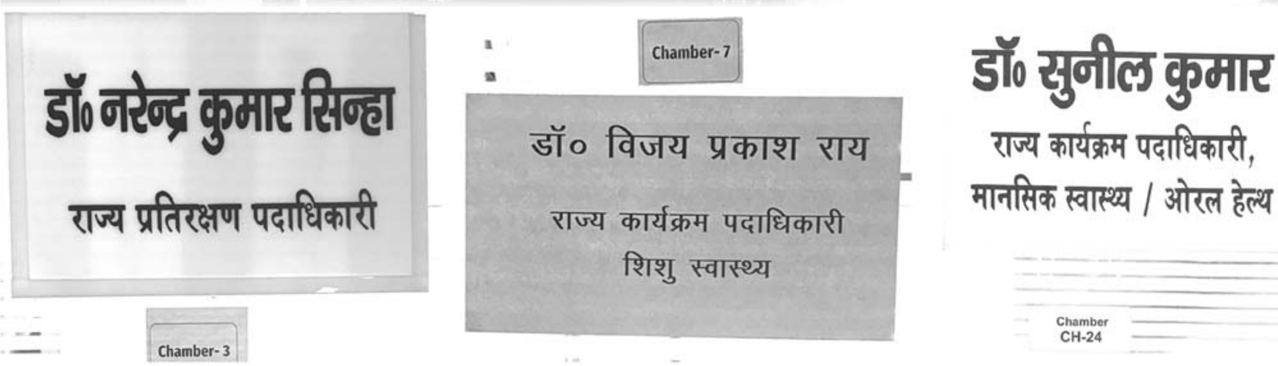

दंत चिकित्सकों के भरोसे बिहार का मानसिक रोग, यक्ष्मा रोग, ब्लड बैंक, अंधापन नियंत्रण, बाल सुरक्षा योजना, एनीमिया मुक्त भारत और टेलीमेडिसिन जैसे मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत शामिल कर लिया गया है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और सुलभ बनाना है, खासकर कमजोर समूहों के लिए। NRHM के मुख्य उद्देश्य :-

☞ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाना।

☞ शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।

☞ संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों को रोकना और नियंत्रित करना।

☞ जनसंख्या नियंत्रण और लिंगानुपात में सुधार करना।

☞ स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।

☞ आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धांत, और होम्योपैथी) को बढ़ावा देना।

☞ स्वास्थ्य क्षेत्र और व्यवस्था में सुधार लाना।

☞ ग्रामीण आबादी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना।

✯ NRHM की शुरुआत :-

☞ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी।

☞ यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी।

☞ 2013 में NRHM को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में शामिल कर लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) भी शामिल है।

✯ NRHM के तहत किए गए कार्य :-

☞ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना।

☞ स्वास्थ्य सेवाओं के ढाँचे में सुधार करना।

☞ स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी।

☞ स्वच्छता और स्वच्छता पर ध्यान देना।

☞ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना।

☞ रोग नियंत्रण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बड़े राज्यों में यह योजना राष्ट्रीय खाओ–पकाऊ योजना होकर रह गई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस योजना ने भारत के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीर बदली है और ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में बड़े-बड़े घोटाले सामने आए कई डॉक्टर और अधिकारियों को आत्महत्या तक करनी पड़ी और कई को लंबी जेल यात्रा करनी पड़ी। कईयो का कैरियर समाप्त हो गया। बिहार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था राज्य स्वास्थ्य समिति में एक-दो हजार करोड़, कई हजार नहीं, कई हजार करोड़ रुपयों घोटाला हुआ है। आज नहीं तो कल राज्य स्वास्थ्य समिति में हुए कई हजार करोड़ रुपयों के घोटाले का राज खुलेगा, तब कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है तो कईयों को आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति को संचालित करने के लिए कार्यपालक निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य कार्यक्रम प्राधिकारी की भूमिका अहम होती है। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से टीकाकरण, आशा गैर संचारी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग, चाइल्ड हेल्थ, टेलीमेडिसिन, रोड सेफ्टी, ओरल हेल्थ कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल कार्यक्रम, अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इस कार्यक्रमों में अधिकांश कार्यक्रमों को दंत चिकित्सक (डेंटिस्ट) संभाल रहे हैं। डॉ० राजेश कुमार सिंह ब्लड बैंक संभाल रहे हैं, जो एक दंत चिकित्सक हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था है। इस तरह डॉक्टर विनय कुमार दंत चिकित्सक पूरे बिहार के मानसिक रोगियों को संभालते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार दंत चिकित्सक राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे हैं, डॉ० राजीव कुमार दंत चिकित्सक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहे हैं, डॉक्टर नीरज कुमार दंत चिकित्सक अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम चला रहे हैं और डॉ० मनीषा कुमारी दंत चिकित्सक टेलीमेडिसिन कार्यक्रम चला रही हैं। दंत चिकित्सक राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला यह दंत चिकित्सक जिनको दांत का इलाज करने के सिवा कुछ नहीं आता है, वह इतने बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम कैसे चला रहे हैं। इनमें से कई दंत चिकित्सक या तो राजनेता, न्यायाधीश, बड़े

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.17505 of 2024

M/s Science House Medicals Private Limited

... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar & Ors.

... ... Respondent/s

with
Civil Writ Jurisdiction Case No. 1377 of 2025

POCT Services,

... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar & Ors.

... ... Respondent/s

Appearance :
(In Civil Writ Jurisdiction Case No. 17505 of 2024)

For the Petitioner/s	:	Mr. Abhinav Srivastava, Sr. Advocate Mr. Nirbhay Prashant, Advocate
For the State	:	Mr. Vikash Kumar, SC-11
For Respondent No. 5	:	Mr. Ravinder Singh, Advocate Mr. Parth Gaurav, Advocate Mr. Govind Raj Shahi, Advocate
For Respondent No. 8	:	Mr. Sekhar Singh, Sr. Advocate Mr. Kumar Shanu, Advocate Mr. Kumar Abhishek, Advocate Mr. Shubham, Advocate Mr. Prasoon Shekhar, Advocate
For the Intervenor	:	Mr. Lalit Kishore, Sr. Advocate Mr. Rajeev Kumar Singh, Advocate
For the SHSB	:	Mr. P.K. Shahi, Advocate General Mr. K.K. Sinha, Advocate

(In Civil Writ Jurisdiction Case No. 1377 of 2025)

For the Petitioner/s	:	Mr. Mrigank Mauli, Sr. Advocate Ms. Madhubala Kumari, Advocate Mr. Amit Anand, Advocate
For the State	:	Mr. Vikash Kumar, SC-11
For the Resp No. 4	:	Mr. Ashish Giri, Sr. Advocate Mr. Kumar Shanu, Advocate Mr. Kumar Abhishek, Advocate Mr. Shubham, Advocate
For the SHSB	:	Mr. P.K. Shahi, Advocate General Mr. K.K. Sinha, Advocate
For Respondent No. 9	:	Mr. Ravinder Singh, Advocate Mr. Parth Gaurav, Advocate Mr. Govind Raj Shahi, Advocate

WEB COPY

Patna High Court CWJC No.17505 of 2024(11) dt.24-03-2025
7/8

participate in the bidding process and no more.

11. This Court having *prima-facie* noticed that the consortium, once having been declared a selected bidder was obliged to form a separate entity with whom the agreement was to be executed, wanted to know the stand of the learned Advocate General.

12. We record that a fair stand has been taken at the Bar by the learned Advocate General in no time, taking a stand that the purpose behind Clause-'3' of Annexure-5 of the 'NIT' document was to allow an agreement to be executed between a legal entity in form of an 'SPV' under the Companies Act and the 'SHSB' and it seems that the agreement should have been executed by 'SHSB' only after formation of the said legal entity.

13. In the kind of stand taken at the Bar by the learned Advocate General representing the 'SHSB', we need not detain ourselves in discussing the various other aspects of the matter which may be well discussed at the stage of final adjudication of the writ petitions.

14. I.A. No. 01 of 2025 is allowed. The amendment as prayed for shall be carried out and the parties, if so advised, may file their respective response within one week from today.

WEB COPY

Patna High Court CWJC No.17505 of 2024(11) dt.24-03-2025
8/8

15. In view of what has been recorded hereinabove and discussed at length in the Court, the learned Advocate General has assured this Court that remedial measures shall be taken by 'SHSB' within this period of one week.

16. We are sure that keeping in view the stand hereinabove, we expect that 'SHSB' shall take remedial measures, cancel the agreement immediately and any action taken pursuant thereto shall be set at naught.

17. The issues raised in the writ application and the amendment application which survive for adjudication, shall remain open for consideration on the next date.

18. As jointly prayed, list these matters on 3rd of April 2025 under the same heading as first case subject to part heard.

(Rajeev Ranjan Prasad, J)

(Sourendra Pandey, J)

aditya/-

U

WEB COPY

अधिवक्ता और राजनेता के सगे संबंधी हैं। इस संबंध में केवल सच में जब राज्य स्वास्थ्य समिति में जानना चाहा तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति में पोस्टिंग मुख्यालय स्तर से होती है।

पूरे राज्य स्वास्थ्य समिति उर्मिला और भव्या के फेर मे सिर्फ डाटा बना रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ घोटाला; जैसे एंबुलेंस घोटाला, पैथोलॉजी निविदा में घोटाला, प्रिंटिंग घोटाला, दवा घोटाला, भाड़े पर गाड़ी लेने में घोटाला, X-RAY घोटाला, अल्ट्रासाउंड घोटाला। अगर इनका घोटाला लिखा जाये तो पूरी पत्रिका भर जाएगी। पैथोलॉजिकल निविदा घोटाला में राज्य के महाअधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय में कबूल किया की गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन मजाल है किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो जाए। भारत सरकार की एजेंसी ED हर जगह रेड कर सकती है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति में जाने से डरती है। क्योंकि भारत सरकार का भी पैसा और भारत सरकार के भी अधिकारी घोटाले में संलिप्त हैं। हमने अपने हर आलेख में कहा है कि पैथोलॉजी निविदा में घोटाला हुआ है। आज न्यायालय में साबित हो गया कि घोटाला हुआ है। केवल सच जो लिखती है, वह सच ही होता है।

हमने राज्य स्वास्थ्य समिति मे राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रशिक्षक की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पटना उच्च न्यायालय के वाद संख्या-MJC-1274/2023 आज भी पटना उच्च न्यायालय में लंबित है और न्यायालय से न्याय की मांग कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने वाले स्वास्थ्य प्रशिक्षक यहां राज्य स्वास्थ्य समिति में स्टेट लेवल के अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के स्वास्थ्य सिस्टम को डैमेज कर करोड़ों की उगाही कर रहे हैं।

राज्य स्वास्थ्य समिति के कुछ अधिकारी का वरदान मिला हुआ है, जिसमें एक नाम है सहायक निदेशक मनीष रंजन। जिसने अपने ईमानदारी और परिश्रम के बदौलत आज बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया है; चाहे बात हो दवाओं की या बात हो ऑक्सीजन प्लांट की या बात हो मेडिकल उपकरण की। मनीष रंजन के कारण राज्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। अगर मनीष रंजन जैसे प्रतिभाशाली अधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति में नहीं होते तो हो सकता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बिहार में फेल हो जाता। राज्य स्वास्थ्य समिति में भगवान चित्रगुप्त की देन है सहायक निदेशक मनीष रंजन। राज्य स्वास्थ्य समिति के कई अधिकारियों ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया की स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव भी गाहे-बगाहे मनीष रंजन से राय लेते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास भी करते हैं। आज मनीष रंजन राज्य स्वास्थ्य समिति का चमकता सितारा बन गये हैं।

एक दिन अंधियारा दूर होगा भ्रष्टाचार पर से पर्दा हटेगा तो राज्य स्वास्थ्य समिति में कायपालक निदेशक सुहर्ष भगत और उनके भ्रष्ट्र अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे और सहायक निदेशक मनीष रंजन का सितारा बुलंद होगा। ●

बिहार में बाबाओं के प्रवचन या चुनावी प्रचार क्या है असल मकसद?

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। हर दल अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करने में जुटा है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ राजनीतिक चेहरे ही नहीं, बल्कि धार्मिक गुरु भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु, प्रवचनकर्ता और संत बिहार का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार हमेशा से जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख

मोहन भागवत का बिहार दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वह राज्य में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। हर बार उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत पड़ी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत

झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे सियासी माहौल पहले ही गर्म हो चुका था और अब धार्मिक गुरुओं की एंट्री ने इसे और गरमा दिया है।

बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के प्रभाव वाले इलाके गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पहुंचना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। धीरेंद्र शास्त्री यहां पांच दिनों तक हनुमंत कथा कर रहे हैं, और उनकी कथाओं में हिंदुत्व का एजेंडा साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं बल्कि हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हालांकि, उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर भीड़ जुटाने की उनकी कला और बीजेपी नेताओं से उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं है। गोपालगंज, जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां जाकर हिंदुत्व पर जोर देना साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। यह रणनीति खासतौर पर बिहार में जातीय राजनीति के मुकाबले धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत करने की कोशिश लगती है। यह पहला मौका नहीं है जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस तरह के बयान दिए हैं, बल्कि वे लगातार हिंदू एकता की बात करते रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को अगर छेड़ा गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे, और यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनावी बिसात बिछ रही है। धीरेंद्र शास्त्री के बिहार दौरे के ठीक बाद आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी बिहार पहुंच गए। उनका भी बिहार दौरा महज आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर ने पटना के गांधी मैदान में सत्संग का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने ध्यान, योग और जीवन जीने की कला पर प्रवचन दिए, लेकिन उनके दौरे की सबसे अहम बात वह 1000 साल पुराना पवित्र शिवलिंग था, जिसे वे बिहार लेकर आए थे। यह वही शिवलिंग है जिसे 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खंडित कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि सदियों से एक अग्निहोत्री परिवार इस शिवलिंग को संभालकर रखे हुए था, और अब इसे सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जगाने और उन्हें एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। श्री श्री रविशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि उनके बिहार पहुंचने के तुरंत बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनसे मिले और बिहार सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन

भागवत भी बिहार में थे। उनका पांच दिवसीय दौरा जारी है, और इस दौरान वे संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भागवत ने अपने इस दौरे में बिहार के लोगों की तारीफ की और कहा कि वे समर्पण, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उन्होंने दशरथ मांझी का उदाहरण देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके सफलता पाई जा सकती है। हालांकि, उनके इस दौरे को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संघ प्रमुख का बिहार आना, वह भी चुनाव से पहले, यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी के लिए बिहार चुनाव हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राज्य में जातीय समीकरण काफी मजबूत हैं। अब तक बीजेपी को जेडीयू के सहारे ही सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। धार्मिक गुरुओं का बिहार में एक के बाद एक पहुंचना और उनके प्रवचनों में हिंदुत्व की बातें करना यह साबित करता है कि बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। आरजेडी ने साफ कहा है कि बीजेपी यह सब चुनावी फायदे के लिए कर रही है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी धार्मिक गुरुओं को आगे कर बिहार में एक नई राजनीतिक धारा बहाना चाहती है।

हालांकि, बीजेपी इस तरह के आरोपों को नकारती रही है, लेकिन यह तो साफ है कि इन सभी घटनाओं का

एक खास मकसद है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन बीजेपी अब इसे हिंदुत्व के आधार पर बदलने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में इसे मजबूती से लागू करने की कोशिश पहली बार इतनी खुलकर हो रही है। संघ भी लगातार इस रणनीति पर काम कर रहा है कि जातियों में बंटे हिंदुओं को एक मंच पर लाया जाए, ताकि इसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहले भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी हिंदू जागरण के लिए यात्रा निकाली थी, और अब बिहार में भी उनका यही उद्देश्य नजर आ रहा है। श्री श्री रविशंकर के महमूद गजनवी द्वारा खंडित शिवलिंग को लेकर बिहार आने का भी यही मकसद हो सकता है कि हिंदुओं की भावनाएं जाग्रत हों और वे एकजुट होकर एक खास विचारधारा के समर्थन में खड़े हों। इन सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ होता है कि बिहार चुनाव से पहले धार्मिक बाबाओं का यह दौरा महज संयोग नहीं, बल्कि एक सियासी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी यह समझ चुकी है कि बिहार में जातीय समीकरणों के चलते उसे सत्ता पाने में दिक्कत होती रही है, इसलिए अब वह हिंदुत्व को केंद्र में रखकर चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह तो चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुत्व का मुद्दा भी पूरी तरह हावी रहेगा। ●

योगी सरकार के आठ साल वाह से आह तक

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं,जबकि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आठ साल पूरा कर चुके हैं। यूपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड भी योगी के नाम हो गया है। करीब 24 करोड़ आबादी को यदि योगी से पूर्व की सरकारों के तौर तरीकों की याद होगी तो वह जानते होंगे कि आठ साल पहले प्रदेश का क्या हाल था। यूपी की गणना बीमारू राज्य के रूप में होती थी। साम्प्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा अखिलेश सरकार की पहचान थी। आतंकवादियों के मुकदमें वापस लिये जाते थे। तुष्टिकरण समाजवादी सरकार की पहचान बन गई थी। दंगा पीड़ितों को उनका धर्म देखकर मुआवजा बांटने का कारनामा भी अखिलेश सरकार द्वारा किया गया था। सपा के नेता थानों तक में गुंडागर्दी करने से घबराते नहीं थे। आजम खान जैसे समाजवादी नेताओं की बदजुबानी के किस्से आम थे। हिन्दू देवी देवताओं का अपमान समाजवादी सरकार की आदत बन गई थी। हाल यह है कि आठ साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अखिलेश की राजनीति नहीं बदली है। विकास के नाम पर अखिलेश एक्सप्रेस वे और लखनऊ में मेट्रो के अलावा कुछ नहीं गिना पाते थे।

एक वह दौर था जब प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी तो अब फाइलों में विकास नहीं उलझता है, बल्कि जमीन पर फलफूल रहा है। अपराधी ठोके जा रहे हैं। भू-माफियाओं से कब्जाई जमीन वापस ली जा रही है। संगठित अपराध करने वालों को चुन चुनकर मिटाया जा रहा है। मगर पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के प्रति धारणा बदलने में सफलता प्राप्त की है। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज व्यवसाय एवं निवेश का सर्वश्रेष्ठ ठिकाना बनकर देश और दुनिया में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज 'ग्रोथ गियर' है। हमें विरासत में अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला था।ऐसे राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुगम कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों द्वारा निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने में हम लोग सफल रहे। विगत आठ वर्षों में प्रदेश को प्राप्त हुए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव इसकी पुष्टि करते हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इनके माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। स्थापित सत्य है कि सुरक्षा के सुपथ पर ही विकास कुलांचे भरता है और सुगम कनेक्टिविटी उसे तीव्रता प्रदान करती है।

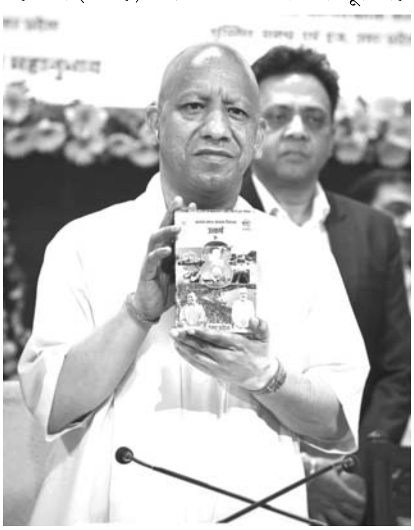

'नया उत्तर प्रदेश' उसका जीवंत उदाहरण है।

महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास ही अंत्योदय है। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की हर योजना में यह भाव श्वास लेता है। यही कारण है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश सरकार ने छह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धनों को प्रतिमाह नि:शुल्क अनाज, 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन, 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.21 करोड़ लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच, 56.50 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क आवास जैसे अनेक कल्याणकारी उपहारों ने प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। सभी को आवास के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी को आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिनके पास भूमि नहीं थी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। यही तो है अंत्योदय।

आजादी से लेकर 2017 तक प्रदेश में 12 मेडिकल कालेज थे। आज राज्य में 44 राजकीय मेडिकल कालेज और 36 निजी मेडिकल कालेजों सहित 80 मेडिकल कालेज संचालित हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन आरंभ हो गया है। 'एक जनपद-एक मेडिकल कालेज' की संकल्पना उत्तर प्रदेश में साकार हो रही है। प्रदेश में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। मार्च, 2017 से अब तक तीन नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है। छह चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। आठ वर्षों में 46.50 लाख गन्ना किसानों को 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, पी.एम.स्वनिधि योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं मातृशक्ति के जीवन में सकारात्मकता का सवेरा लेकर आई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2,510 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन, ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) घर की महिला के नाम आदि जैसी

रचनात्मक पहल नारी शक्ति के जीवन में सम्मान और आर्थिक प्रगति का प्रतीक हैं। प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का युगांतरकारी कार्य किया है। वर्ष 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी जो अब तीन प्रतिशत है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये विभिन्न आयोगों एवं भर्ती बोर्ड द्वारा साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। इनमें से 1.38 लाख से अधिक महिलाएं हैं। परीक्षाओं के शुचितापूर्ण आयोजन के लिए उ. प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) कानून लागू किया

गया है, जिससे छात्रों के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास जागा है। आठ वर्ष हमारी आस्था, अस्मिता, आर्थिकी और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल-पेट्रोल दरें देश में सबसे कम हैं। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे रामराज्य की अवधारणा ही है।

खैर, योगी राज में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश की सत्ता योगी तक केन्द्रित हो कर रह गई है। बीजेपी तक के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। योगी का सख्त आदेश है कि कोई विधायक सिफारिश लेकर किसी अधिकारी या थाना-चौकी पर नहीं जायेगा, परिणाम स्वरूप ब्यूरोक्रेसी और पुलिस निरंकुश हो गई है। योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने और नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। सरकारी भर्तियों में देरी, पेपर लीक की घटनाएं और युवाओं को अपेक्षित संख्या में नौकरियां न मिलना एक बड़ी चुनौती रही है। वहीं योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के दावे काफी किए, लेकिन कई विभागों में रिश्वतखोरी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें बनी हुई हैं। खासकर तहसील, थाने और नगर निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बढ़ी है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलने, फसलों के उचित दाम न मिलने और बिजली की बढ़ती दरों से किसान परेशान रहे हैं। सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए 'ठोक दो' नीति अपनाई, लेकिन पुलिस की मनमानी, फर्जी एनकाउंटर और निर्दोष लोगों पर अत्याचार के आरोप भी लगे। थानों में दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सुनवाई न होने की शिकायतें अक्सर आती रही हैं। योगी सरकार की बुलडोजर नीति को एक तरफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे पक्षपातपूर्ण और गरीबों के खिलाफ करार देता है। कई मामलों में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए ही घरों और दुकानों को ढहा दिया गया, जिससे विवाद हुआ। उधर, कई सरकारी योजनाओं की घोषणाएं हुई, लेकिन उनका लाभ सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया। पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना और स्वरोजगार योजनाओं में भ्रष्टाचार और भेदभाव की काफी शिकायतें सामने आई हैं।कुल मिलाकर योगी सरकार की वाह-वाह भी खूब हो रही है,वहीं कुछ लोगों को लगता है कि योगी राज में जनता कराह रही है। उसकी आह को कोई सुनने वाला नहीं है।●

मिशन-2027 की तैयारी
यूपी में नया चेहरा लाने की तैयारी में भाजपा

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही दो साल बाद होने वाले हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में आई कमी ने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राज्य में जनाधार कैसे मजबूत किया जाए और 2027 में सत्ता की हैट्रिक कैसे बनाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। हाल ही में 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर मंथन शुरू हो चुका है। पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है, जो न केवल संगठन को मजबूत कर सके, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की राह भी आसान बना सके। बीजेपी के संविधान के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तब किया जा सकता है जब 50 प्रतिशत से अधिक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी हो। इस बार 71 प्रतिशत से अधिक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है और वे जल्द ही लखनऊ का दौरा कर सकते हैं। पार्टी का पूरा ध्यान ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर है, जो पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सके।

उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर को देखें तो बीजेपी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं की अगुवाई में लड़े थे। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य और 2022 में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और दोनों चुनावों में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी पार्टी किसी ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) गठजोड़ के सहारे बीजेपी को तगड़ी चुनौती दी थी और कई सीटों पर बढ़त हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण का राजनीति पर गहरा असर पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं और पूर्वांचल में उनकी गहरी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य जातीय समूह के नेता को सामने लाकर संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। चर्चा में आए संभावित नामों में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल हैं। इनमें से धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि दिनेश शर्मा ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन सिर्फ जातीय समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठनात्मक कुशलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए विपक्ष के मजबूत गठबंधन से मुकाबला करना होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राज्य में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, जो चुनावी रणनीति को सही दिशा

केशव प्रसाद मौर्य

दिनेश शर्मा

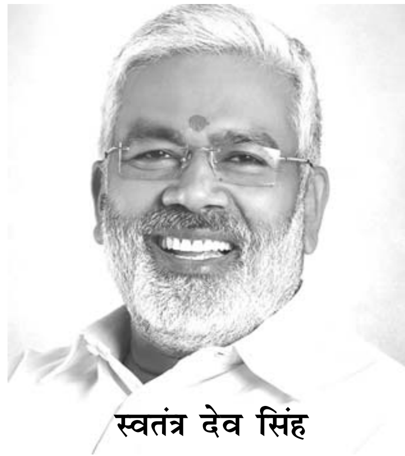
स्वतंत्र देव सिंह

बी.एल. वर्मा

में ले जा सके और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है, जो सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रख सके। पिछले कुछ वर्षों में संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई बार यह बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच यह धारणा बनी थी कि योगी सरकार में उनकी सुनवाई कम हो रही है और नौकरशाही का दखल बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत है, जो न केवल संगठन को मजबूत करे, बल्कि सरकार और संगठन के बीच किसी भी तरह के टकराव को भी रोके। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में दिल्ली और लखनऊ के बीच संतुलन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो, जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों को समझे और उन पर अमल करे, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी अच्छे तालमेल के साथ काम करे।

इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनका योगी सरकार के साथ अच्छा तालमेल था। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर कई बार सवाल उठे। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे नेता की तलाश की जा रही है, जो सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठा सके और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके।

बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव में पार्टी को नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। 2017 और 2022 में पार्टी ने विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झटका लगा क्योंकि विपक्ष ने जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया था। ऐसे में 2027 के चुनाव में बीजेपी को सामाजिक समीकरणों को

ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही चुनावी रणनीति को जमीन पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का एक और महत्वपूर्ण दायित्व उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर असंतोष देखने को मिलता है। 2022 के

धर्मपाल सिंह

विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर गलत उम्मीदवारों के चयन की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, जो न केवल मजबूत संगठनकर्ता हो, बल्कि टिकट बंटवारे में भी निष्पक्षता और संतुलन बनाए रख सके। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद बीजेपी पूरी तरह से मिशन-2027 में जुट जाएगी। पार्टी का मुख्य लक्ष्य अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही नए वोटरों को भी जोड़ना होगा। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। बीजेपी की कोशिश है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो, जो पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी को चुनावी मोड में ला सके और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए प्रेरित कर सके। अभी तक बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है और जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाती है और वह चेहरा पार्टी को 2027 में सत्ता की हैट्रिक दिलाने में कितना सफल होता है।●

योगी कैबिनेट में बदलाव और नये बीजेपी अध्यक्ष की सुगबुगाहट

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)

भारतीय जनता पार्टी के लिये उत्तर प्रदेश हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। सबसे अधिक सांसद और राज्य के तौर पर सबसे अधिक विधायक देने वाला यूपी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेजतर्रार राजनीति के कारण हिन्दुत्व की प्रयोगशाला बन गया है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि इसके बाद 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को यहां से करारा झटका भी लगा था,यूपी में 70 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी गठबंधन को मात्र 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी,जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 42 एवं आजाद समाज पार्टी को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे योगी की छवि पर काफी बुरा असर पड़ा। अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए)का दम भरने लगे,परंतु विधान सभा के उपचुनाव में योगी फिर से मुखर होकर उभरे उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से चित कर दिया। इसके बाद अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी। मिल्कीपुर के मतदाताओं ने जाति बिरादरी से ऊपर बीजेपी को वोट किया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी की सियासत में काफी बदलाव आ चुका है। उस पर महाकुंभ सोने पर सुहागा साबित हुआ,जहां जातपात से ऊपर उठकर 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पूरा प्रदेश ही नहीं देश भी हिन्दू मय हो गया। इन बदलावों के बाद अब योगी कैबिनेट में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। वहीं यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा के साथ संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। इस बात के कयास तब से लगना शुरू हुए जब दिल्ली में प्रधानमंत्री से योगी की मुलाकात हुई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 09 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान सीएम योगी ने पीएम से अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन का समय मांगा, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के कयास लगाए जाने लगे हैं. बता दें महाकुंभ आयोजन के बाद सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे. प्रधानमंत्री से मुलाकात से एक दिन पूर्व सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। बता दें यूपी में बीजेपी के नये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लम्बे समय से मंथन चल रहा है, वहीं योगी कैबिनेट में 6 मंत्री पद भी खाली हैं. ऐसे में जेपी नड्डा और पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात को सरकार और संगठन में बदलावों पर सहमति बनाने के रूप में देखा जा रहा है. होली के बाद बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना तय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि योगी सरकार में भी फेरबदल होगा।

गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी दो साल बाकी हो, लेकिन हर समय चुनाव के लिये तैयार रहने वाली बीजेपी ने अभी से 2027 के यूपी विधान सभा चुनाव के लिये सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बीजेपी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका दिया. बीजेपी का सवर्ण–पिछड़ा–दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया था. हालांकि, विधानसभा उपचुनाव

आते-आते सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को चारो खाने चित कर दिया था, तभी सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार बीजेपी जमीन पर काम करती दिख रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि नवरात्रों में योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. योगी सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने लोकसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होना है. ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की योगी कैबिनेट में वापसी हो सकती है, क्योंकि संगठन की बागडोर संभालने से पहले मंत्री रहे हैं.

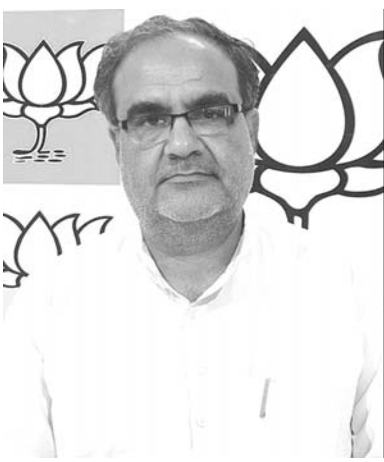

बता दें योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं. इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं. इस तरह से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित है. इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों में अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की थी. इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि नवरात्रि में योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण समझा जा रहा है. बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहना सकती है. बात सपा की कि जाये तो समाजवादी पार्टी जिस तरह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जिताऊ फॉर्मूला तैयार कर रही है, उसे मंत्रिमंडल के चेहरों से काउंटर करने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है. इसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की रणनीति है.

उत्तर प्रदेश में जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है. मंडल अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है. जिला अध्यक्ष की सूची में कुछ पेंच की वजह से अभी तक जारी नहीं की जा सकी है. ऐसे में सीएम योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के बदलाव पर चर्चा कर सहमति बनाने का फार्मूला निकाला होगा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं. बीजेपी के लिए यूपी काफी अहम है. इसलिए, अध्यक्ष के चुनाव में कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है. 2022 में जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी सीएम योगी से ट्यूनिंग का ख्याल रखा गया था. अब नए प्रदेश अध्यक्ष में भी इस बात का ख्याल रखा जाना तय माना जा रहा है. माना जा रहा है कि होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा का भी निर्धारण हो जाएगा. बीजेपी संगठन में फेरबदल कर विपक्षी सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है. बीजेपी के संगठन में जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है. बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे रही है. लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी, लेकिन बीजेपी 80 फीसदी वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. यूपी संगठन बीजेपी की रणनीति तमाम जातियों को जगह देकर जमीनी स्तर पर सामाजिक समीकरण को साधने की है. सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में लड़ाई 80-20 की होने वाली है. मतलब समझाते हुए वे कहते हैं कि बीजेपी 80 फीसदी भाग पर कब्जा जमाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20 फीसदी सीटें आने वाली हैं. इस तरह बीजेपी की नजर 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, जिसके लिए ही सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है. ऐसे में कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव कर एक मजबूत सियासी आधार तैयार करने की रणनीति है?●

बीजेपी बनाम सपा

गौशाला और इत्र पार्क पर छिड़ी सियासी जंग

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)**

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में गौशालाओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वे गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है, इसलिए उन्होंने इत्र पार्क बनाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और कहा कि अखिलेश यादव की यह टिप्पणी हिन्दू परंपराओं का अपमान करने के बराबर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान न केवल गाय के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि यह हिंदू संस्कृति और आस्था पर हमला भी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति में उलझ चुकी है और इसी कारण इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बयान ने उनकी पार्टी के भीतर भी विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पार्टी के अंदरखाने में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि गाय हमारी माता है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल आधार ही समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना है और ऐसे बयानों से पार्टी की छवि प्रभावित होती है। अखिलेश यादव पहले भी कई बार अपने बयानों के कारण विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राणा सांगा को लेकर भी एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे उनकी पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, उन्होंने औरंगजेब को लेकर भी कुछ ऐसा कहा था जिससे हिंदू मतदाताओं में नाराजगी देखी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति को बचाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह रणनीति उनके परंपरागत यादव वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। यादव समाज का गौ-सेवा से पुराना रिश्ता रहा है। महाभारत काल से लेकर आज तक यादव समुदाय में गाय को लेकर विशेष

सम्मान देखा गया है। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं यादव कुल में जन्मे थे और उनका जीवन गौ-सेवा में ही बीता। आज भी देश में यादव समुदाय गाय को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट करता है और उसे अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानता है। मुलायम सिंह यादव भी गौ-सेवा में विश्वास रखते थे और उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा था कि उनके पास जितनी गायें हैं उतनी किसी और नेता के पास नहीं होंगी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गौशालाओं को लेकर कई योजनाएं भी बनाई थीं।

अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हिन्दू आस्था का अपमान बताते हुए कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और यह समाज को बांटने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस बयान की आलोचना की और कहा कि अखिलेश यादव अब पूरी तरह से अपनी राजनीतिक दिशा भूल चुके हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं। अखिलेश यादव का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी अपनी हिंदुत्व की राजनीति को और मजबूत कर रही है और अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को और आक्रामक बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव के इस बयान से उनका परंपरागत यादव वोट बैंक भी उनसे खिसक सकता है।

गाय और गौशालाओं को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान से समाज के कई वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गौ-सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे सनातन धर्म का हिस्सा माना जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और खेती में किया जाता है। कई भारतीय घरों में आज भी गौ-सेवा की परंपरा कायम है। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान न केवल राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, बल्कि यह समाज

के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव से अपील की है कि वे अपने बयान को स्पष्ट करें, ताकि इससे होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इस पर सफाई दें और कहें कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। यह पहला मौका नहीं होगा जब अखिलेश यादव को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी हो। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों से पलट चुके

हैं।

बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता इसे हिंदू आस्था से जोड़कर दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाना जाता है और अब इस बयान के बाद बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की आईटी सेल इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार कर रही है और अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव वोट बैंक का विशेष महत्व है। बीजेपी लंबे समय से यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह संदेश दिया था कि वे यादवों को भी सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार में भी यादव समुदाय से कई मंत्री बनाए गए हैं। इन सबके जरिए बीजेपी यह बताना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की तरह ही बीजेपी भी यादवों की हितैषी है। ऐसे में यदि अखिलेश यादव इसी तरह विवादित बयान देते रहे, तो यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति के जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। गाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राजनीति में धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर बयान देते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़े होते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है। क्या अखिलेश यादव इस बयान से पीछे हटेंगे, या फिर अपने बयान पर कायम रहेंगे, यह देखना बाकी है। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही और आने वाले चुनावों में यह बयान सपा के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए यह समय राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अगर अखिलेश यादव सही रणनीति नहीं अपनाते हैं, तो आगामी चुनावों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति को धार देने में लगी हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव के इस तरह के बयान बीजेपी को ही फायदा पहुंचा सकते हैं।अंततः यह स्पष्ट है कि राजनीति में बयानबाजी करते समय नेताओं को सतर्क रहना चाहिए, ताकि उनके शब्द समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाएं और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।●

मुख्यमंत्री ने 'हर घर नल का जल' निश्चय अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं एवं भवन संरचनाओं का किया शिलान्यास

● **अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 18 मार्च को 1, अण्णे मार्ग स्थित 'संकल्प' में रिमोट के माध्यम से 'हर घर नल का जल' निश्चय अन्तर्गत 7,166 करोड़ 6 लाख रूपये लागत की जलापूर्ति योजनाओं/भवन संरचनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 83 करोड़ रूपये लागत की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार ने बताया कि राज्य के लोगों को नियमित व निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राज्य सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति कर रही है जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। 'हर घर नल का जल' निश्चय अन्तर्गत निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की 'हर घर नल का जल' योजना की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है उसे ससमय पूर्ण करें। 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करते रहें। सभी चीजों का मेंटेनेंस हो। हमलोगों का उद्देश्य है कि लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गयी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव श्री संजीव कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी जुड़े हुये थे। ●

पूरी तरह से कदाचारमुक्त रही सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा : जितेंद्र कुमार

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के विज्ञापन संख्या 01/2023 में विज्ञापित बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा (च्म्ज्) दिनांक 09.12.2024 से 10.03. 2025 तक शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना में आयोजित की गयी। परीक्षा के आयोजन के लिए पर्षद द्वारा व्यापक व्यवस्थाएँ की गयी थीं। पर्षद के पदाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय द्वारा तैनात पुलिस पदाधिकारियों, स्थानीय जिला प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से परीक्षा कदाचारमुक्त एवं विधि-व्यवस्था समस्या मुक्त वातावरण में सम्पन्न की गयी। परीक्षा के संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा 316 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी, जिसमें 07 पुलिस अधीक्षक स्तर एवं 20 पुलिस उपाधीक्षक एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी सम्मिलित हैं। PET परीक्षा के लिए 1,07,079 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें से 86.539 अभ्यर्थी भौतिक रूप से सम्मिलित हुये, इनमें 53,960 पुरुष, 32,569 महिला एवं 10 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थी शामिल हैं। 3 महीना से अधिक अवधि तक चले इस परीक्षा कार्यक्रम में 72 कार्यदिवसों में परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें 43 दिन पुरूष एवं 29 दिन महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गयी। प्रत्येक दिन अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता, शारीरिक माप एवं उनके अभिलेख सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) को सुचारू रूप से एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए पर्षद द्वारा व्यापक तकनीकी व्यवस्थाएँ की गयी। अभ्यर्थियों की उपस्थिति, उनकी पहचान तथा पररूपधारण करने की संभावना को नकारने के लिए आवेदन के फोटो, लिखित परीक्षा के समय लिये गये फोटो, बायोमेट्रिक चिह्नों तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान उनके फोटो, फिंगर प्रिंट तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का सहारा

लिया गया। इसके साथ ही दौड़ में समय की गणना के लिए त्थ्फ्‌ एवं सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग एवं अन्य स्पर्धाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से अत्याधुनिक तकनीकों से कार्य सम्पन्न कराया गया, जिससे सूचनाओं के संग्रहण में मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सके। ऊँचाई आदि के माप-तौल में भी मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिससे सटीक सूचनाएँ संकलित की जा सकी। पूर्व में अंकित प्रक्रियाओं के आधार पर ही इस परीक्षा के दौरान 462 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गयी जिन्होंने परीक्षा में पररूपधारण अथवा अन्य कूटकर्म से परीक्षा परिसर में भाग लेने अथवा उसमें अभ्यर्थियों को सहयोग करने के प्रयास किए, इनमें 370 अभियुक्त इस परीक्षा के अभ्यर्थी थे। ऐसे तत्वों के विरूद्ध 37 काण्ड स्थानीय थाना गर्दनीबाग, पटना में दर्ज किये गये। काण्ड दर्ज करने के समय हीं इनमें से 84 अभ्यर्थियों को जेल भी भेजा गया, अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान एवं तत्संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस तरह तकनीक के प्रयोग से अवांछित तत्वों द्वारा परीक्षा तंत्र को अतिक्रमित करने के प्रयासों को प्रभावहीन किया जा सका।परीक्षा के दौरान 110 अभ्यर्थियों को चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ी, जिसे परीक्षा स्थल पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारियों एवं स्थानीय अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। कुल मिलाकर शारीरिक दक्षता परीक्षा का यह वृहद आयोजन प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य सहयोगी एजेन्सियों, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवा, नगर निगम प्रशासन तथा सबसे महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों के सहयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा (च्म्ज्) में पास अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी दलाल प्राकृति के व्यक्ति के झांसे में न आएँ कि वह उनके अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में किसी प्रकार की मदद कर सकता है। यह उसके द्वारा अवैध धन उगाही का तरीका हो सकता है, जिसमें भोले-भाले अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावक फंस सकते हैं और मेहनत की कमाई से हाथ धो सकते हैं, साथ ही कानूनी कार्यवाही के भी भागी हो सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रकार पर्षद द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न की गई है, उसी प्रकार शेष कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण कर अंतिम चयन अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारों को भेजी जाएगी, जिसमें स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन का आधार केवल और केवल उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेधा सूची में अर्जित स्थान होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थियों को इस प्रकार से सम्पर्क करता है अथवा पर्षद के प्रतिनिधि के रूप में सम्पर्क करने का प्रयास करता है तो ऐसे तत्वों की सूचना स्थानीय थाना, साईबर अपराध थाना अथवा आर्थिक अपराध इकाई को दें, जहाँ से उनके द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) कदाचार मुक्त, शुचिता पूर्ण एवं भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध है।●

- ☞ अत्याधुनिक तकनीक की मदद से संपन्न हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा।
- ☞ अभिभावक व अभ्यर्थी दलालों के झांसे में ना आएं।

जनमानस के लिए योजनाओं को सुलभ बना रही हैं जीविका दीदियाँ

● **पूनम जायसवाल**

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर सशक्त तो हो ही रही है सरकार की योजनाओं को भी धरातल तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं स जीविका के संबल से इन ग्रामीण महिलाओं ने जीविका दीदी के तौर पर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उन योजनाओं को आम जनमानस के लिए सुलभ बना रही हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित हुई महिलाएं भारत सरकार के उज्ज्वला सखी कार्यक्रम के अंतर्गत मिनी गैस एजेंसी का संचालन कर रही हैं। इसे उर्जा स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। उर्जा स्टोर मिनी गैस एजेंसी के तौर पर कार्य करती हैं और इसके लिए सौर स्टोर संचालक जीविका दीदी और गैस एजेंसी धारक के बीच करार होता है। उज्जवलासखी कार्यक्रम अंतर्गत उर्जा स्टोर चलाने वाली महिलाओं को उज्जवला सखी नाम दिया गया है। उज्ज्वला सखियां मौजूदा सूक्ष्म उद्यमी हैं जो किराना दुकान, सिलाई केंद्र, श्रृंगार स्टोर और ग्राहक सेवा केंद्र या इसी तरह के सूक्ष्म उद्यम का संचालन करते हुए सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है। वे अपने उज्ज्वला सखी व्यवसाय से जो आय अर्जित करती हैं, वह उनकी समग्र कमाई को पूरक बनाती है।

उज्ज्वला सखी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सुदूर गांवो में उर्जा स्टोर खोले जारहे हैं जहाँ कोई भी गैस एजेंसी की पहुँच नहीं हैं स प्रावधान के तहत उर्जा स्टोर का आवंटन स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं को दिया जाता है। उर्जा स्टोर संचालक महिलाएं कनेक्शन धारकों को मिनी गैस एजेंसी के तौर पर वो सारी सुविधाएँ प्रदान करती हैं जो एक गैस एजेंसी द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में भी जीविका से संबद्ध स्वयं सहायता समूह से जुडी उन महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर दिया जा रहा है, जो सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित हैं और स्वरोजगार कर रही हैं। श्रीमती किरण देवी अपने गाँव में मिनी गैस एजेंसी के तहत उज्ज्वला सखी कार्यक्रम अंतर्गत उर्जा स्टोर का संचालन कर रही हैं। उनके द्वारा उर्जा स्टोर पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी प्रखंड के सिकरिया गाँव में अक्तूबर 2023 से संचालित है। किरण देवी उर्जा स्टोर से भारत गैस वितरक के साथ गैस रिफिलए नया कनेक्शन; उज्ज्वला एवं सामान्य श्रेणियों के अंतर्गतद्ध, दूसरा सिलेंडरए पोर्टबिलिटी आदि सुविधा के साथ ही गैस चूल्हा और सुरक्षा गैस पाइप अदि की बिक्री कर रही हैं। उर्जा स्टोर से किरण देवी को प्रति माह 6 से 7 हजार रुपये की आमदनी हो रही है। प्रवधान के तहत प्रतिदिन गैस सिलेंडर की स्टोरेज और बिक्री ग्राहकों को बाजार मूल्य पर करती हैं।

श्रीमती किरण देवी सतत् जीविकापार्जन योजना की लाभार्थी हैं। दीदी सतत जीविकापार्जन योजना के तहत सिलाई और श्रृंगार का दूकान का संचालन कर रही हैं। इस योजना का लाभ लेकर दीदी अपने बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा भी मुहैया करवा रही हैं। किरण देवी के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना और उज्ज्वला सखी कार्यक्रम वरदान से कम नहीं हैं। किरण देवी बताती हैं कि अब से 7 साल पहले खेतों में मजदूरी करके जो मेहनताना मिलता था, उसी से अपने तीन बेटी और पति के लिए भोजन उपलब्ध करा पाती थी। पति बीमार रहने के कारण कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। किरण देवी की परेशानी को देखते हुए उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना से श्रृंगार दुकान के लिए सहयोग प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में तुलसी जीविका महिला ग्राम संगठन से उनके नाम का अनुमोदन होने के बाद उन्हें श्रृंगार दुकान के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं विशेष निवेश निधि के तहत सहयोग प्रदान किया गया। इसके साथ ही सात माह तक एक.एक हजार रूपया अंतराल राशि भी मिली। जीविका से मिले सहयोग ने उनके जीवन की दिशा एवं दशा बदल दी है। उर्जा स्टोर के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों को उर्जा क्रांति का आगाज हुआ है। वर्तमान समय में 10 सौर स्टोर का संचालन बिहार के 06 जिला यथा सीतामढ़ी, सारण, वैशाली, पटना, रोहतास और कटिहार में उज्जवला दीदी के तौर पर जीविका दीदियों द्वारा जारी है। अन्य जिलों में भी उर्जा स्टोर प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। ऊर्जा स्टोर के खुलने से ग्रामीण महिलाओं के आय में वृद्धि के साथ ही सुदूर गांवो में और आस-पास के लोगों को नजदीक में ही गैस से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। साथ ही लोक कल्याणकारी योजनायें भी सुदूर गांवो में जीविका दीदियों द्वारा सुलभता से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ●

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ने चयनित पैक्सों को किया पुरस्कृत

● मुकेश कुमार

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग डॉ0 प्रेम कुमार ने आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना (वित्तीय वर्ष 2024-25) के चयनित कुल 46 पैक्सों को बीते 21 मार्च को पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मे पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के अधीन राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार (15 लाख रूपये) समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के सरायरंजन पश्चिमी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि0 को, राज्य स्तरीय द्वितीय पुरस्कार (10 लाख रूपये) बेगूसराय जिला के मटियानी प्रखंड के सोनापुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि0 सोनापुर को तथा राज्य स्तरीय तृतीय पुरस्कार (7 लाख रूपये) पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड के मियापुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि0 को प्रदान किया गया। इसके अलावे अन्य कुल 43 पैक्सों को भी जिला स्तरीय प्रथम (5 लाख रूपये) द्वितीय (3 लाख रूपये) तृतीय (2 लाख रूपये) पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉ0 प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले पैक्सों को न सिर्फ कार्यकुशलता में वृद्धि होगी बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वे उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित होंगे, जिसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों एवं किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसका उद्धेश्य पैक्सों को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यो के लिए पुरस्कृत करना तथा पैक्सों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण करना है जिससे कि पैक्स अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित हो सके। माननीय मंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति कार्य पर प्रशन्नता व्यक्त करते हुए पैक्स अध्यक्षों से 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने वाली रवी विपणन मौसम 2025-26 में गेहूं अधि प्राप्ति कार्य को भी तत्परता से करने की अपील की, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके।

माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 को 'अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है और आगामी 30 मार्च 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में पटना के ज्ञान भवन में इस कार्यर्क्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कुल 46 पैक्सों को राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना हेतु पैक्स से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.01.2025 थी। इस निर्धारित अवधि में पूरे बिहार से कुल 1129 पैक्सों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया। जिला स्तरीय कमिटी द्वारा योग्य पैक्सों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के उपरांत इसे प्रमंडल स्तरीय कमिटी स्तर

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना (2024–25) के तहत जिलास्तीरय पुरस्कार हेतु चयनित पैक्सों की सूची निम्न है :–

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पैक्स का नाम	प्रथम/ द्वितीय/तृतीय	अनुशंसा	पुरस्कार की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सारण	मशरक	नवादा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
2.		बनियापुर	मनिकपुरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
3.	मुंगेर	तारापुर	माणिकपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
4.	जमुई	सिकन्दरा	महादेव सिमरीया प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
5.	खगड़िया	आलौली	हथवन प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	प्रथम	जिला स्तर पर	5.00
6.	बेगूसराय	मटियानी	बलहपुर 02 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
7.		बीरपुर	नौला प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
8.	अरवल	कलेर	पहलेजा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	प्रथम	जिला स्तर पर	5.00
9.		कलेर	टेरी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
10.	जहानाबाद	हुलासगंज	मुरगांव प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
11.		काको	अमथुआ प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
12.	नवादा	कौआकोल	दरावां प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
13.	औरंगाबाद	रफीगंज	इटार प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
14.		देव	बेढना प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
15.	मधुबनी	मधेपुर	महिशाम प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
16.		लखनौर	दीप पूर्वी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
17.	सीतामढ़ी	बैरगनिया	पताही प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	प्रथम	जिला स्तर पर	5.00
18.	मधेपुरा	सिहेश्वर	रूपौली प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
19.		सिहेश्वर	सुखासन प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
20.	सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	खजुरी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
21.		सत्तरकटैया	बिजलपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
22.	सुपौल	बसंतपुर	रतनपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	प्रथम	जिला स्तर पर	5.00
23.		पिपरा	थुमहा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
24.		निर्मली	कुनौली प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
25.	समस्तीपुर	विभूतिपुर	साखमोहन प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
26.	अररिया	भरगामा	खुटहा बैजनाथपुर पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
27.		फॉरबिसगंज	शहबाजपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
28.	किशनगंज	किशनगंज	टेउसा पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
29.	गोपालगंज	गोपालगंज	तिरबिरवों प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	प्रथम	जिला स्तर पर	5.00
30.		फुलवरिया	पकौली बाड़ो प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
31.		सिघवलिया	जलालपुर कला पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
32.	सिवान	भगवानपुर हाट	मिर्जुमला प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
33.		दरौंली	दोन बुजुर्ग प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
34.	मुजफ्फरपुर	सरैया	बहिलवारा रूपनाथ दक्षिणी पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
35.	पश्चिम चंपारण	मैनाताड	सुखलही प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
36.	पटना	बिहटा	नेउरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
37.		नौबतपुर	चिरौरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
38.	नालंदा	एकंगरसराय	तेलहाडा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
39.	पूर्वी चम्पारण	पकरी दयाल	राजेपुर नवादा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
40.	वैशाली	पातेपुर	बरडीहा तुर्की प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
41.	कैमूर	रामपुर	जलालपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00
42.	रोहतास	रोहतास	नावाडीह प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	द्वितीय	जिला स्तर पर	3.00
43.		संझौली	चांदी इंग्लिश प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०	तृतीय	जिला स्तर पर	2.00

पर अग्रसारित की गई। प्रमंडल स्तरीय कमिटि द्वारा इस अग्रसारित पैक्सों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के उपरांत कुल 141 योग्य पैक्सों की अनुशंसा राज्य स्तरीय कमिटी को की गई। राज्य स्तरीय कमिटी द्वारा बिहार के तीन सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले पैक्सों का भी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। राज्य स्तरीय कमिटी द्वारा गहन समीक्षा एवं जाँच के उपरांत कुल 43 पैक्सों को जिला स्तर पर योग्य पाया गया, जिन्हें पुरस्कृत करने हेतु चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत, राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पैक्स को पुरस्कृत किया जाता है। पैक्सों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। पैक्सों का चयन त्रिस्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में तथा राज्य स्तर पर अपर निबंधक (साख) सहयोग समितियों की अध्यक्षता में समिति गठित है। इस समारोह में अस्थावां के विधायक श्री जितेन्द्र कुमार, गुरूआ के विधायक श्री विनय कुमार यादव के साथ सहकारिता विभाग के सचिव, श्री धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियाँ, श्रीमती इनायत खान, अपर सचिव, श्री अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक (साख), सहयोग समितियाँ श्री प्रभात कुमार एवं बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री रमेश चौबे, पाटलिपुत्रा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री रितेश कुमार, गोपालगंज सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री महेश राय, बेगुसराय सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री नरेंन्द्र सिंह, वैशाली सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री सुधी रंजन सहित सहकारिता विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। ●

2019 में दिया हुआ 8000 करोड़ का प्रस्ताव
बिहार के बंद पड़ी आठ चीनी मिल को खोलने का था

● त्रिलोकी नाथ प्रसाद

बिहार में सरकार निवेश की बात करती है लेकिन जब निवेशक यहां उद्योग धंधे करने को लेकर निवेश का प्रस्ताव देते है तब नीतीश सरकार के अधिकारी अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर निवेशकों के सामने बिहार में सैकड़ो तरह की समस्या का हवाला देकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं जिसकी भनक तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं लगती हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हैं साल 2019 में दिया हुआ 8000 करोड़ का प्रस्ताव जो बिहार के बंद पड़ी आठ चीनी मिल को खोलने का था। मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 24 अक्टूबर 2019 को एक आवेदन उद्योग विभाग बिहार को दियास जिसमें उसने एक प्रस्ताव दिया कि वह बिहार के बंद पड़ी आठ चीनी मिल बनमनखी (पूर्णिया), हथुआ एवं हथुआ डिस्टलरी (गोपालगंज) ,वारसलीगंज (नवादा) गुरारू (गया) न्यू सिवान (सिवान) सिवान (सिवान) लोहट (मधुबनी) गोरोल (वैशाली) को पुनर्जीवित करने का काम करेगें। इसके बाद उन्हें 6 दिसंबर 2019 को यह बताया गया कि क्योंकि गन्ना विभाग ने आपको आठ बंद पड़ी चीनी मिल का जमीन उपलब्ध नहीं कराया है और आपके पास जमीन नहीं है इसलिए आपके प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया है इसी बीच आनन फानन में कुछ विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से मुख्यमंत्री के कैबिनेट में एक प्रस्ताव के माध्यम से यह बातें सामने आई कि बंद पड़ी सभी 8 चीनी मिल की जमीन, भवन, मशीनरी और स्क्रैप बियाडा को हस्तांतरित किए जाएंगे साथ ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार इस भूमि को बियाडा अधिनियम 1974 के अंतर्गत लीज पर आवंटन कर उससे प्राप्त राशि बियाडा द्वारा नियम अनुसार सरकार के कोष में जमा की जाएगी इसके बाद मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बियाडा से दोबारा आग्रह किया कि बिहार की बंद पड़ी सभी चीन मिल की जमीन उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह उसे चालू कर सके। इस बीच एक बार पुनः गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य निवेश प्रोत्साहन

परिषद के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से आग्रह किया की क्योंकि बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन और ऐसेट हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में है और मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनका प्रस्ताव SIPB में लंबित है इसलिए अनुरोध है कि मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पटना बिहार का अभ्यावेदन पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के आग्रह के बाद 18 दिसंबर 2020 को मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया की 23.12. 2020 को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव कार्यालय में अपने पूरे प्लान और पूरी टीम के साथ उपस्थित हो। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रधान सचिव वित्त प्रधान, प्रधान सचिव गन्ना उद्योग सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे और इस बैठक में मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति भी बनी लेकिन लंबे समय तक मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किसी भी तरह की कोई जानकारी बिहार की बंद पड़ी चीनी मिल को खोलने के संदर्भ में नहीं दी गई, जबकि इस मिल के चालू होने से करीब एक करोड़ किसानों को नगदी फसल का फायदा होता साथ ही 25 हजार स्थाई और 20 हजार दैनिक मजदूर को रोजगार उपलब्ध होता इसके अलावे 240 मेगावाट बिजली के उत्पादन के साथ 56000 टन गन्ना का पेराई होता 4 लाख 80 हजार इथेनॉल प्रतिदिन उत्पादन किया जा सकता था। इसके साथ ही 250 करोड़ वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती जिससे बिहार आज वंचित रह गया। जैसा की सर्वविदित है बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तभी से मुख्यमंत्री बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश और विदेश का दौरा करते रहे हैं और बिहार में हर साल बिजनेस कनेक्ट/बिजनेस समीट/बिजनेस कानक्लेव का आयोजन भी होता रहा है लेकिन यहां उम्मीद के मुताबिक कंपनिया अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाई है। ऐसे में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2021 को और 9 मार्च 2021 को दो बार महत्वपूर्ण बैठक की गई,

जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने 2016 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई है और किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस पॉलिसी को बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेशक आएंगे इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही बंद चीनी मिलों की शुरुआत होगी एवं नए चीनी मिल भी स्थापित होगी। उपमुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई जिसमें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार सहित बिहार सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, उद्योग सचिव, वित्त सचिव, सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे थे लेकिन फिर भी मेसर्स रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिहार के सभी बंद पड़ी आठ चीनी मिल को खोलने का आदेश निर्गत नहीं हो सका। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है की बिहार के कुछ भू माफिया बिहार के बड़े अधिकारियों से सांठ-गांठ कर बियाडा से जुड़ी जमीनों का सौदा करते हैं और अवैध रूप से कमाई करते हैं, लेकिन जो निवेशक बिहार के आर्थिक हालात को ठीक करना चाहते हैं, बिहार के किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं उन लोगों से सरकार के अधिकारी मुँह मोड़ लेते है जिससे बिहार से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। ●

प्रधनमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को सहायता राशि का मुख्यमंत्री ने किया एकमुश्त हस्तांतरण

● **अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 मार्च को 1, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रूपये की सहायता राशि का माऊस क्लिक कर एकमुश्त हस्तांतरण किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत सर्वप्रथम सितम्बर, 2024 में 2,43,903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 से 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रूपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार 40 प्रतिशत अर्थात् 48 हजार रूपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है।

ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 07 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 1.05 लाख लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया था। इस पर 420 करोड़ रूपये का व्यय हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में 03 लाख लाभार्थियों को 40 हजार रूपये की दर से प्रथम किश्त की राशि

का एक मुश्त भुगतान किया गया। इस पर कुल 1200 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। आगामी 100 दिनों में इन लाभुको को द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में 80 हजार रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा। साथ ही इन लाभुकों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रूपये तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। इस प्रकार प्रति लाभुक 1,54,050 (एक लाख चौवन हजार पचास) रूपये दिये जायेंगे। इस प्रकार इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए 3 लाख लाभुकों को आगामी लगभग 100 दिनों में 4621.50 करोड़ रूपये प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है उन्हें बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई देता हूँ। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लाभुकों को तुरंत लाभ मिले। लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा, मनरेगा की आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि जिलों से जिलाधिकारी एवं कुछ लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे। ●

बिहार विधानसभा चुनाव में एक-एक सीट को तरसेगा विपक्ष?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

एनडीए बिहार में फिर अपनी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष एक-एक सीट को तरस जाएगा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि कौन तरसेगा राजद या भाजपा ? पिछले चुनाव में याद करें कि तेजस्वी यादव अकेले 75 सीट लाकर दिखला दिया दूसरी ओर भाजपा को लाज बचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी मैदान में उतरना पड़ा उसके बावजूद भी 74 सीट पर ही सिमट गये। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि बिहार के भाजपाईयों ने समाज के बीच में पहचान नहीं बन सका। तेजस्वी यादव किसी एक मंच पर आ जाए तथा बिहार के सभी भाजपाई दूसरे मंच पर आ जाए उसके बावजूद भी संख्या में बराबर नहीं कर सकता है। दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आज तक बिहार में मुख्य मंत्री काबिल कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी सवाल है कि तेजस्वी यादव अपना चेहरा दिखलाने में शर्माते नहीं है। समाज के बीच में रहना है। दूसरी और बिहार के भाजपाई का ? कोई चेहरा देख न ले इस कारण ऐसी रूम में रहते हैं। बिहार के भाजपाई

सिर्फ तीन ही मंत्र सीखा है कार्यकर्ताओं से नारा लगवाना, माला पहनना और फोटो खिंचवाना, और यही मंत्र सिखलाते भी है।बिहार के भाजपाई यदि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को घर-घर तक पहुंचा दी जाती तो बिहार में भाजपा के यह दुर्गति नहीं होती।

एक बैठक को संबोधित करते हुए डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि उम्मीद से अधिक सफलता मिल रही है। एनडीए कार्यकर्ता भगवान सूरज से ऊर्जा प्राप्त कर चट्टानी एकता के साथ लक्ष्य की ओर निरंतर आगेग्ध की बढ़ रही हैं। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि उत्साह देखते ही बनता है लगता है कि विधानसभा चुनाव में सीटों से भी ज्यादा मतलब 243 से ही ज्यादा है सीट पर जीत हासिल कर सकती हैं। यह अहम कितना सफलता दिखाएगी आने वाले समय ही बताएगा।●

दिल्ली से बिहार तक जाएगा भाजपा का जोश, यह भारी भूल

बिहार में किसके विरूद्ध लड़ेगी राजद, कांग्रेस या माले?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार विधानसभा का अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने है। परिस्थितियों कभी भी करवा सकती हैं। कड़े संघर्ष एवं लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी पर विजय से भाजपा का आत्म बल बढ़ा है। दिल्ली में कांग्रेस को बहुत नजर अंदाज करके नहीं चला जा सकता है। दिल्ली में वह हारी जरूर हैं, लेकिन मकसद को बचा कर रखा है। कांग्रेस अब नए तेवर के साथ राजद कि ओर सहयोग का हांथ बढ़ाकर ज्यादा सीट मांग सकती है। बिहार के राजनीत में तीन ही चेहरा है। तेजस्वी यादव,चिराग पासवान और नीतीश कुमार। भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। सिर्फ मोदी पर भरोसा है। तेजस्वी के साथ मुस्लिम और यादव मिलाकर लगभग 33 प्रतिशत वोटर हैं इसके अलावा भी दुसरी जाती में भी अच्छी पैठ है। तेजस्वी यादव अकेले विधानसभा चुनाव 75 सीट ला दिया ।चिराग पासवान के साथ पासवान के अलावा सभी जातियों में पैठ है। चिराग पासवान का क्षमता है कि अपने भले ही नहीं जीत पाए परंतु 40/ 45 सीट पर जदयू और भाजपा को भी ला देगी। भाजपा के पास बिहार में कोई

चेहरा नहीं है कि लाज बचा सके। अगले बार भाजपा को लाज बचाने के लिए बिहार के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा उसके बावजूद बिहार में 74 सीट पर सिमट गए। कितना शर्मनाक है की बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद भी 74 सीट सिमट गया। बिहार के भाजपाई अंधा, गूंगा बहरा की जमात बनगई है, जिसे , सत्ता के चश्मा से नहीं अपराध झलकती है और नहीं भ्रष्टाचार जबकि पूरा बिहार अपराध का नगरी औरग्ध भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। अपराध और भ्रष्टाचार एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। मोदी जी द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को यदि घर घर पहुंचा दी जाती तो भाजपा का स्थिति काफी मजबूत हो जाती।

जन सुराज पार्टी को दो घोषणा भारी नुकसान पंहुचा सकती है। शराब चालु करने की घोषणा तथा 40 सीट मुस्लिम को घोषना कर भारी नुकसान कर चुके हैं। चर्चा पर विश्वास करें तो मुस्लिम वोट राजद का है। नीतीश कुमार को भले ही लग रहा है कि मुस्लिम वोट मेरा है।●

भाजपा में ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं अनील कुमार शर्मा सदैव आंधी तूफानों का सामना किया

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति लिखने का साहस कर रहा हूं ,जिसने सदैव आंधी तूफानों का सामना किया किसी के आगे झुक नहीं। बिना किसी भयके, बिना किसी स्वार्थ के सदैव आगे बढ़ता रहा? जिस व्यक्ति के जीवन का मूल मंत्र रहा अपने कर्तव्य, कर्म को ही सर्वोपरि समझ कर अपनी कुशलता तथा बुद्धिमता का परिचय दिया, ऐसे प्रतिभा कोई परिचय का मोहताज नहीं। यह पटना जिला अंतर्गत फतुहा के गोविंदपुर मोहल्ला निवासी तथा इनका अपना मां तारा उत्सव पैलेस है। इनके साहस स्पष्ट वादिता व निरपक्षिता की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। वह समुचे परिवार भाजपा को समर्पित है। उन्होंने अपना मैरिज हॉल को भाजपा कार्यालय के रूप में बगैर कोई मूल्य का समर्पित कर दिया। यही नहीं ऐसा भी देखा गया है कि भाजपा का अचानक बैठक होने की आवश्यकता होने पर पूर्व में मैरिज हॉल का सट्टा का पैसा भी वापस कर दिया तथा भाजपा कार्यक्रम के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ गया। अनिल कुमार शर्मा का ईमानदारी, ईमानदारी देखकर भाजपा नगर के मंडल अध्यक्ष शोभा देवी ने भाजपा नगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का उपाधि दिया। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पटेल का संगठन बनाने एवं भाजपा कैसे मजबूत हो का गहरी सोंच तथा कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ाना देखकर अनील कुमार शर्मा ने 21 हजार रुपए केंघ चेक से सम्मानित तत्कालीन जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह द्वारा करवाए। मंच पर उपस्थित केशव कांत,राणा राजेंद्र पासवान,संजय यदुवेंद्र ,अरुण कुमार झा, रामजी प्रसाद ,अरविंद यादव, पासवान शोभा देवी शामिल थे।मंच पर उपस्थित शोभा देवी एक ऐसी महिला थी जिसने मंडल अध्यक्ष का पद देश में दूसरी महिला थी। प्रथम महिला थी सुषमा स्वराज, दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तथा भारत का विदेश मंत्री थी। शोभा देवी ने भाजपा का मान और सम्मान बढ़ाया। अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि शोभा देवी को जिला अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शोभा जब मंडल अध्यक्ष थी तो फतुहा का रुतबा बदल गया था। अनिल कुमार शर्मा ने अश्रु पूर्ण स्वर में कहा कि मेरा पुत्र अंकुश कुमार ईमानदार की मूर्ति तथा फतुहा भाजपा नगर के मंत्री था जिसे पद से हटा दिया गया। यही फतुहा भाजपा की ओर से उपहार दिया गया। मुझे यहां के भाजपा से दिल टूट गया सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे परिवार हूं।●

घूसखोर को पकड़ने के लिए विजिलेंस, जहां दोबारा कोई नहीं जाता

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया जिला प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार के नजरों में जनता एक मूर्ख का जमात है। घूसखोर को पकड़ने के लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है। घूसखोर को पकड़वाने के लिए अपना पैसा जमा करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिलचस्प मामला है कि विजिलेंस से पकड़वाने वाले व्यक्ति दोबारा कभी नहीं जाता। सरकार ने एक नया योजना बनाई है कि अब रिश्वत खोरो को पकड़्घ्वाने के लिए पैसा सरकार देगी। सरकार के नजरों में घूसखोरों को पकड़ने का मामला बढ़ेंगे क्योंकि कई मामलों में जितने पैसे मांगी जाती थी उससे संबंधित व्यक्ति राशि फंसने के चक्कर में शिकायत नहीं करते हैं। अब सरकार पैसा देगी इसलिए घूसखोरी को पकड़ने में की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी गंभीर विषय है की जनता को मूर्ख बनाने की योजना है। एक बार जो व्यक्ति रिश्वतखोर को रंगे हाथ पकड़वा दिया वह कभी सपने में भी रिश्वतखोर को नहीं पकड़वाएगा आएगा। मैं इसका स्वयं उदाहरण हूं। पटना सिटी कोर्ट की घटना 30/ 12/77 की है। घूस मांगा डीसीएलआर चंद्रशेखर रजक तथा जेल गया पारस नाथ तथा चपरासी जगदीश राम। चंद्रशेखर रजक दौड़ कर भागने में सफल हुआ। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि सचमुच में घूसखोरी रोकना है तो ऐसे विभागों के पदाधिकारी को साल में एक बार नार्को टेस्ट करवा दें। ऐसे घोषणा होते ही कोई भी पदाधिकारी घूस लेने के लिए स्वप्न में भी नहीं सोंचेगी, उन्हें डर होगी कि ऐसे आदेश सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। रिश्वतखोर लोग कहीं न्यायालय में पहुंच जाए कि हम लोग की तरह ही सभी विधायक, सांसद, मंत्री को भी साल में एक बार नारको टेस्ट करवाने की आदेश दी जाए। यदि न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर दी जाएगी तो सरकार के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकती है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी ऐसे कानून बनाकर घूसखोरी रोका जाए।●

हां मैं किसान हूं, किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में मृत्यु?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

किसानों के शरीर से बहता हुआ पसीना और मिट्टी में मिलकर फसलों के साथ तासीर बनाने वालों की दशा देश में अच्छी नहीं कही जा सकती है। जबकि यह सत्य है कि जिस दिन किसानों का पसीना खेतों में बहना बंद हो जाएगा, उस दिन अन्न के लिए लोग तरसते दिखेंगे। बावजूद किसानों के नियति और जिंदगी नासूर से कम नहीं है। जिस देश के किसान खुशहाल और समृद्ध नहीं होंगे उस देश की तरक्की और विकास शीलता की तीव्रता कुंद हो जाएगी। हालात आज भी ज्यों का त्यों है। आजादी के सात दशक बद भी लघु ,सीमांत ,किसान और किसान मजदूर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश में प्रतिवर्ष किसाने की संख्या में परिवर्तन होता जा रहा है। जो 10 /20 वर्ष पूर्व किसान थे आज किसान मजदूर बन गए हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों ने किसानों की जमीन औने- पौने दाम पर खरीद कर किसानों को भूमिहीन बना दिया है। सरकार की नीति और नियति भी किसानों के प्रति सही नहीं कहीं जा सकती है। किसानों को अपनी फसलों को तैयार करने और उसे उपजाने में जितना पूंजी और मेहनत लगता है, उसके हिसाब से उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान उन्नत बीज, रासायनिक खाद, यूरिया खाद, डीएपी, फास्फेट, जिंक, पोटास एवं कीटनाशक दवाइयां के लिए अपनी सारी पूंजी लगा देता है। यहां तक की जीस महाजन से किसान ब्याज पर पैसे लेकर खाद, बीज, खरीद करता है। पांच से दस वर्षों में उसके खेत उसी महाजन के यहां इजारा या बिक जाती है। हम अपनी फसल और उत्पादित वस्तुओं को कीमत स्वयं तय नहीं कर सकते हैं। हमसे हमारी गाढ़ी कमाई कूड़े के भाव खरीद लिए जाते हैं और बाद में वही वस्तुओं की कीमत आसमान पर होती है। आज भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ,बिहार, बंगाल आदि राज्यों में अन्न का उत्पादन अन्य राज्यों के अपेक्षा सबसे अधिक होती है। खासकर हम अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा पटना ,नालंदा, जिले में धान और गेहूं के अलावे सब्जी की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह की फसलों के साथ लीची, केला, आम, मखाना, आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के मामले में नालंदा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर ,वैशाली जिला अब्बल है। लेकिन सब्जियों के भंडारण और उचित बाजार नहीं रहने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिहार के उत्तर बिहार के दर्जनों जिले बाढ़ से प्रभावित होती है। वहीं दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे की चपेट में आ जाती है। आज देश में नहीं जमीदार है और नहीं अंग्रेज है फिर भी हुकूमत करना चाहिए हिटलर से काम नहीं है।

आज है आधुनिक भारत, जहां बड़े-बड़े उद्योगपतियों को और अरबों खरबों का ऋण माफ हो जाता है, और किसानों को ऋण के लिए कुर्की ,जप्ती और गिरफ्तार की जाती है। किसानों का समस्या समाधान कैसे होगी इस संदर्भ में एक किसान एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों से अनाज 100 किलो राज्य सरकार खरीदे। तथा सामान्य रेट 20/25 रुपए किलो बाजार को दे। सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। सरकार वेतन घटाए। पूंजी पत्तियों का बेटा यदि कम वेतन पर नौकरी करना न चाहे तो किसान सिर्फ अन्न ही देना नहीं जानती है बल्कि अपने पुत्रों को शिक्षित कर शिक्षक से लेकर के सिपाही, दरोगा, डीएसपी,एस पी, सीडीपीओ बीडीओ, सीओ आदि सबों पदों के लिए 30 हजार से 40 हजार रुपए महीना पर देने को तैयार हैं। किसान राज्य सरकार के अधीन होती है, किसान के समस्या राज्य सरकार को करनी होगी।●

मुख्यमंत्री एक महीना का समय दें, बिहार की सूरत बदल दूंगा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह भाजपा मीडिया प्रभारी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है की एक महीना समय दें। बिहार के सूरत बदल दूंगा? बिहार में सबसे बड़ी समस्या है अपराध और भ्रष्टाचार ?। अपराध रोकने के लिए सर्वप्रथम कारतूस का प्राइवेट दुकान बंद कर देना होगा तथा यह दुकान बिहार के डीजीपी कार्यालय में सरकारी दुकान होगी। लाइसेंसी हथियार को इस्तेमाल करने के कारण बताना होगा तथा इस्तेमाल किए हुए कारतूस के खोल को यह वापस करना होगा? अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियार को बरामद करना अनुसंधानकर्ता को अनिवार्य होगी तथा हथियार निर्माण स्थल का उद्वेदन भी करना अनिवार्य करना होगा। इससे अपराध में 90/ प्रतिशत कमी आ जाएगी। अपराधियों को हथियार कहां से उपलब्ध होता है इसकी जानकारी प्राप्त करके उसे केंद्र को समाप्त करना होगा क्योंकि हथियार ही अपराध को बढ़ावा देता है। हरेक मोहल्ला एवं गांव में दो चौकीदार बहाली होगा , प्रत्येक दिन हरेक घर जाकर समस्या की जानकारी उपलब्ध करनी होगी।

☞ **भ्रष्टाचार कैसे रुकेगी :-** भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सड़क, पुल,भवन आदि से जुड़े सरकारी इंजीनियर, कृषि जिला पदाधिकारी, स्कूल इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर आदि को साल में एक बार नार्को टीक्स करवाना होगा। इससे काफी फायदा होगा। भ्रष्टाचार में गोता लगाने वाले नौकरी छोड़कर भागेगा तथा ईमानदार अधिकारी ही नियुक्त होंगे। शादी में तिलक दहेज रोकने के लिए शादी में लड़का के पिता या माता को तिलक लेने के संबंध में नारकोटिक्स अनिवार्य होगी। जाति बंधन तोड़ने के लिए अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दी जाएगी। अंतर्जातीय विवाह करने पर पति या पत्नी को नौकरी दी जाएगी। एक शर्त होगी कि अपने से कमजोर वर्ग के लड़की से शादी करनी होगी। लड़का के रंग और रूप की लड़की से ही शादी होगी यह नहीं कि लड़की परी होगी।

☞ **किसानों की समस्या का समाधान :-** किसानों के अनाज का मूल्य लगभग 100 रुपए प्रति किलो निर्धारण करनी होगी। सवाल होगी कि पैसा कहां से आएगा। पैसा के लिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन घटाना होगा। 30 हजार से कम नहीं 60 से ज्यादा नहीं। आज पुरे देश में बेरोजगारी है, 30 हजार रुपए से लेकर 60 हजार रुपए में ही ईमानदार और सभी पदों के लिए मिल जाएगा। चपरासी से लेकर आई एस और आइपीएस तक मिल जाएगा।●

धूमधाम से संपन्न हुआ अखंड पूजन

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मसौढ़ी प्रखंड के भैसवाँ पंचायत में मेघनी बिगहा ग्राम में धूमधाम से अखंड सभी ग्रामीणों द्वारा किया गया। मानव देह भगवान का सबसे अमूल्य वरदान है। भगवान नाम का गुणगान एवं जप करने के लिए यह शरीर मिला है। भगवान के नाम को जपते हुए इस संसार रूपी जीवन में सद्गति प्राप्त किया जा सकता है। इस अखंड का आयोजन इसी ग्राम के कैप्टन विजय कुमार एवं उनके सुपुत्र रविन्द्र कुमार द्वारा किया गया। रविन्द्र कुमार भारतीय स्टेट बैंक पटना में शाखा प्रबंधक हैं। आज इस कलयुग में भगवान का नाम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन विजय कुमार द्वारा 24 घंटे अखंड का आयोजन मेघनीबिगहा के शिव मंदिर में कराया गया। इस मानव शरीर के कल्याण के लिए राम, कृष्ण, शिव, राधा का जप करना अनिवार्य है। यह एक आध्यात्मिक जन कल्याण का पहल हैं, जो काफी सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। इस अखंड के समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मेघनी बिगहा ग्राम में शिव मंदिर की स्थापना 1985 में हुई थी।

महाशिवरात्री के दिन भक्तिमय माहौल रहा। सभी ग्रामीणों ने भगवान राम, कृष्ण, राधा, शिव नाम का गुणगान एवं भजन किया। कबीर साहब ने ठीक ही कहा है :-

भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार!
मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार!!
लुटि सकै तो लूटि लौ, राम नाम की लुटि!
फिर पाछे पछिताहुगे, यही तन जैहि छुटि!!
लुटि सकै तो लुटि लौ, राम नाम भंडार!
काल कंठ तै गहेगा, रूधे दसे दुवार!!
कबीर कुत्ता राम का, मौतिया मेरा नाम!
गले राम की जेवड़ी, जित खेचें तिल जाऊँ!!
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा!
तेरा तुझको सौंपता, क्या लागै है मेरा!!
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नही!
प्रेम गली अति साकरि या में दो ना समाही!!

इस अखण्ड को सफल बनाने में मुख्य भूमिका में मुकुल कुमार (राजद महासचिव) एवं फ्रेंड्स क्लब मसौढ़ी के महासचिव (ओल्ड) ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके साथ ही राजकुमार (पूर्व सरपंच), पप्पू कुमार, रवि रंजन, सुनील कुमार, विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार, जय कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी पूर्व वार्ड सदस्य महापति देवी, राकेश कुमार, राजू कुमार, डॉ. नागेशर (होम्योपैथिक, मसौढ़ी), अशोक कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी शर्मिला देवी (सी.एम. जीविका), साधु प्रसाद (पूर्व मुखिया) एवं रंजय कुमार ने पूरे अखण्ड के माहौल को भक्तिमय बनाया। सभी ग्रामीण भगवान के भजन कीर्तन में झूम उठे। इस अखंड में न केवल मेघनी बिगहा बल्कि पूरे पंचायत के लोगों एवं मसौढ़ी के लोगो ने भी शिरकत की।●

हिलसा में बनेगा सम्राट अशोक भवन

● सोनू यादव

नगर परिषद शहर के वार्ड संख्या 5 में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। नगर परिषद के द्वारा भवन निर्माण को लेकर मंगलवार को भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। भूमि पूजन में एसडीओ प्रवीण कुमार, डीसीएलआर राजन कुमार, मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि अब जल्द ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।भवन बनने के बाद शहर में विभागीय व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बेहतर साधन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होनें बताया कि इस भवन के निर्माण पर 1 करोड़ 69 लाख खर्च होंगे। इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से न सिर्फ सरकारी बल्कि आम कार्यक्रम भी आयोजित कराना आसान हो जाएगा। समझा जाता है कि अन्य सरकारी भवन की तरह इसे भी आवंटित करने के लिए नप द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा।नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सम्राट अशोक भवन के निर्माण के बाद शहरवासियों को एक बड़ा सभागार उपलब्ध होगा, जिसमें लोग राजनीतिक व सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंण्डल मुख्यालय में सरकारी व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक भी भवन नही है भवन नही होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया की पुरानी डीएसपी कार्यालय के पीछे खाली भू भाग करीब 11 डिसमिल में बनने वाले सम्राट अशोक भवन के सभा कक्षा में 500 लोगों के बैठने की जगह होगी। सभा कक्ष के मंच को आकर्षक बनाने की योजना है। सम्राट अशोक भवन दो मंजिला होगा। पहले तल में सभा कक्ष के साथ दो गेस्ट रुम और दूसरे तल पर भी दो गेस्ट रुम बनाए जाएंगे। इसके अलावे गार्ड रूम, वेटिंग हॉल एव पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण होगा। भूमि पूजन के मौके पर उपमुख्य पार्षद प्रतिनिधि शिवजी कुमार, वार्ड पार्षद सन्तोष कुमार गुप्ता, अलवेला प्रसाद, पिंटू कुमार, अभिषेक कुमार, नीरज कुमार, सोनू कुमार, उमेश यादव आदि मौजूद रहे।

☞ भवन के बनते ही शहरवासियों को नप प्रशासन देगा बड़े सभा कक्ष का सौगात

☞ वातानुकूलित बनेंगे सम्राट अशोक भवन, 5 सौ लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था

☞ **सम्राट अशोक भवन बनने से शहरवासियों को मिलेगा सुविधा :-** नगर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण होने से शहरवासियों को काफी हद तक सहूलियत मिलेगी।कारण यह कि हिलसा सिर्फ नगर परिषद ही नही है बल्कि अनुमंण्डल मुख्यालय है लेकिन सुविधा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यहां सौ-दो सौ लोगो को एक साथ बैठने की बेहतर व्यवस्था या मीटिंग हॉल, सर्किट हाउस कुछ भी नही है। एक मात्र छोटा सा सर्किट हाउस डाकबंगला के पास बना है उसमें आगे से मार्केट बनने के बाद जगह कम पड़ने के साथ लुक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्टेशन रोड में पूर्व एलॉटमेंट जमीन पर धर्मशाला बना था वह भी अब किसी के हाथों बेचा जा रहा है। यहां के लोग हमेशा से सर्किट हाउस निर्माण के लिये मांग को दुहराते आ रहे थे। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित सम्राट अशोक भवन बनने से जहाँ प्रशासनिक महकमे के अलावे शहरवासियों को भी कम कीमतों में बेहतरीन सुविधा मिलेगी।

☞ **500 क्षमता बाली वातानुकूलित होगा भवन :-** बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में तैयार किया जाना है। इस भवन ग्राउंड फ्लोर के साथ 60 प्रतिशत सभा के लिये जिसमे 500 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी। जबकि स्टेज के साथ कुर्सी और डेस्क के साथ वेटिंग हॉल की व्यवस्था होगी। भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। पुरुषों एव महिलाओं के लिये अलग अलग प्रसाधन कक्ष, शौचालय , पेयजल , स्नान घर, विजली एव रसोईघर और गार्ड के रहने का कमरा होगा। भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, आवासन में सुविधा होगी।यह भवन नगर परिषद के अधीन में रहेगा।

मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा सम्राट अशोक भवन निर्माण के लिये कब का ही मंजूरी मिल चुका था। जमीन को लेकर मामला लंबित चल रहा था। नगर परिषद में हमारा सरकार बनने के बाद इस दिशा में लगातार प्रयास जारी रखा। जहाँ जिला अधिकारी शशांक शुभांकर के द्वारा जमीन अधिग्रहित करने का निर्देश देकर सभी बाधाए दूर करने में उनका अहम योगदान रहा।उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक भवन निर्माण पर लगभग 1.69 करोड़ खर्च किया जाना है ।।भवन पूरी तरह से वातानुकूलित व सुविधायुक्त होगा। भवन बनने से शहरवासियों को काफी सहूलियत होगी।उन्होंने संवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।●

बाहापर में भव्य मटका समारोह का हुआ आयोजन

● सोनू यादव

दिनांक 15 मार्च को होली के दिन ग्राम पंचायत राज साध के ग्राम बाहापर में गोकुल वासियों, ब्रज वासियों के तर्ज पर गौधुली के वेला में मटका समारोह का आयोजन किया गया। यदुवंशी गोधूलि के बेला में रंग गुलाल का भरपूर इस्तेमाल कर आंनद लेते रहें। मटका समारोह सौहार्दपूर्ण एवं शांतिमय माहौल में मनाया गया। मटका समारोह के पहले एक कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें विजेता टीम को 11000 रुपए इनाम के तौर पर दिया गया। मटका फोड़ने के कार्यक्रम में मटका फोड़ने वाले टीम को 22000 रूपए का नगद भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्राम पंचायत राज सांध के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रण विजय कुमार और राजद के जिला सचिव शशि कुमार ,केवल सच मासिक पत्रिका के कार्यालय संवाददाता सोनू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को भेंट स्वरूप गमछा का वितरण किया और इन्हीं के द्वारा नगद राशि पुरस्कार के तौर पर प्रदान की गई। मौके पर राहुल यादव, दीपक यादव,लाल केशबर यादव, ज्वाल यादव,उधेश यादव, रंजीत यादव, उमेश यादव, रितेश यादव,गोलु यादव, प्रिंस कुमार, विक्की यादव, नौलेश कुमार, शेखी यादव, अंशु कुमार, दिलखुश कुमार, शैलेश कुमार, मुकेश यादव, अविनश कुमार, सचिन कुमार,कौशल यादव, बंटीं कुमार, रजनीश कुमार, अभय कुमार, विकास कुमार, रामा कुमार, मंचूश कुमार, गुड्डू कुमार, चंदन कुमार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

16 घंटे में पुलिस ने किया पॉक्सो कांड का उद्भेदन

● सत्यम शिवम

बैजनाथपुर थाना अंतर्गत दिनांक 24 नवंबर 24 को संध्या समय करीब 8:00 बजे सा0 बैजनाथपुर अंतर्गत कांड के वादी राजकुमार स्वर्णकार की 7 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी का संजीत यादव उर्फ राहुल यादव पिता अनिरुद्ध यादव सा0 गम्हरिया थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा के द्वारा वादी के घर में घुसकर बलात्कार किया जाने का आरोप लगाया गया। संदर्भ में पीड़िता के पिता राजकुमार स्वर्णकार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. संजीत यादव उर्फ राहुल यादव पिता अनिरुद्ध यादव सा0 गम्हरिया थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा के विरुद्ध महिला थाना कांड संख्या - 32 / 24 दिनांक 24 नवंबर 24, धारा - 65 (2), ठ.छ.ै. एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया।

उक्त कांड का अनुसंधान भर पु0अ0नि0 डोली रानी थानाध्यक्ष महिला थाना के द्वारा स्वयं ग्रहण किया। अनुसंधानकर्ता है पु0अ0नि0 डोली रानी के द्वारा अनुसंधान भार ग्रहण करने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिसमें अनुसंधानकर्ता के अलावे सदर थाना के पु0अ0नि0 पुष्पम भारती, पु0अ0नि0 खुशबु कुमारी एवं बैजनाथपुर थाना के पु0अ0नि0 दिनेश कुमार को शामिल किया गया। उक्त घटित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आसूचना संकलन कर गंभीर प्रवृत्ति के कांड में सही दिशा में अनुसंधान करते हुए संलिप्त अप्राथमिक अभियुक्त मिथिलेश कुमार पिता योगेंद्र यादव सा0 बैजनाथपुर, वार्ड नंबर 23 थाना बैजनाथपुर जिला सहरसा की संलिप्त पाते हुए 16 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।●

36 घंटे में संजू हत्याकाण्ड के आरोपी गिरफ्तार

● सत्यम शिवम

सलखुआ थानाध्यक्ष को रात्रि में क्षेत्र अंतर्गत ग्राम - कोपरिया शर्मा टोला, वार्ड नंबर 24 में संजू कुमार पिता - मकलू शर्मा को पूर्व के विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा गोली मार देने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, पुलिस निरीक्षक सिमरी बख्तियारपुर, अंचल थाना अध्यक्ष सलखुआ के साथ तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा घटना को संरक्षित किया गया घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु एफ.एस.एल. की टीम को बुलाया गया। उक्त जख्मी को उनके परिजनों एवं घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा इलाज हेतु सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल सहरसा में कराया गया।

इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर सलखुआ थाना कांड संख्या-46/25, दिनांक-10 मार्च 25, धारा-103(1)/61 (2)/3(5) भा0न्या0सं0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। घटना के तुरंत उदभेदन एवं अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर के नेतृत्व में S.I.T. का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस घटना के आरोपी अमरदीप कुमार शर्मा (जिसके द्वारा गोली मार हत्या की गई थी) पिता स्वर्गीय गागर शर्मा सा0 कोपरिया शर्मा टोला, थाना सलखुआ, जिला सहरसा को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया एवं इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद किया गया। घटना में शामिल आरोपी रवि कुमार शर्मा पे0 मुंशी शर्मा सा0 कोपरिया शर्मा टोला, थाना सलखुआ, जिला सहरसा को त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 11 मार्च 25 को गिरफ्तार का न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का मृतक का पूर्व से विवाद चला रहा था। दिनांक 10 मार्च 25 को पूर्व की विवाद को लेकर इन दोनों के द्वारा यह घटना कार्य किया गया।●

जनता का काम करना ही मेरा धर्म : मदन कुमार

● प्रो० रामजीवन साहु

जमुई बिहार प्रांत का 38 वां जिला है। यह 21 फरवरी 1991 में जिला का दर्जा प्रप्त किया। जमुई एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। त्रेतायुग और द्वापरयुग के आज भी कुछ पदचिन्ह यहां हैं। खैरा प्रखंड में एक गिद्धेश्वर स्थल है,जहां जटायु नाम का एक गिद्ध ने लंकापति रावण के साथ उस समय युद्ध किया,जब रावण सीता माता का अपहरण कर इसी मार्ग से लंका ले जा रहा था। द्वापरयुग में पांडवों का एक वर्ष का अज्ञातवास लक्ष्मीपुर प्रखंड से सटा भीम बांध के जंगल में ही हुआ था। पांडव पुत्र भीम ने वहां एक बांध बांधा था, जो आज भीम-बांध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग कलियुग भी जैन धर्म के दो- दो तीर्थंकर को जन्म देकर जमुई को और अति जगजाहिर कर दिया। जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ का जन्म सदर जमुई प्रखंड के काकन गांव में और जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म खैरा प्रखंड के हरखाड़ पंचायत के जन्मस्थान नामक स्थान में हुआ था। यह जिला पहाड़-पहाड़ियों, जंगलों, झाड़ियों और बरसाती नदियों से भरा पड़ा है।यह दृश्य आर्थिक दर्ष्टिकोण से अति लाभकारी नहीं है, परन्तु ये दृश्य प्राकृतिक छटा में और चार चांद लगा देता है। अब तो केन्द्र और बिहार सरकार भी पर्यटक स्थल बनाने हेतु यहां अरबों रूपये खर्च कर रही है।

जमुई जिले में 1528 गांव,153 ग्राम पंचायत, 16 पुलिस स्टेशन, 10 प्रखंड हैं। पिछले जनगणना के अनुसार यहां की आवादी 17,60,405 है। जिसमें 9,16,064 पुरुष और 8,44,341 महिलाएं हैं। अर्थात पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1000-921 है और साक्षरता दर 62.16% है। यहां की जनता 32.1% अंगिका, 25.29% मगही,36.28% हिन्दी, 5.69% उर्दू और .66% संथाली भाषा बोलते हैं। जमुई जिला के 34 वें पुलिस अधिक्षक श्री मदन कुमार आनन्द हैं। इनके नाम में कुल तीन अक्षर हैं। इस नाम में एक भी मात्राएं नहीं है। बिना मात्रा वाले नाम में कुछ न कुछ अवश्य विशेषताएं गुण रहता है। मदन नाम में भी विशेषताएं हैं। जैसे- म+द+न=मदन। म से मधुर ,द से दयालु और न से नम्र। अर्थात जिन कुमार की वाणि मधुर, स्वभाव दयालु और व्यवहार नम्र हो, वही कहलाते हैं मदन। ऐसे काबिले तारीफ, ईमानदार, पुरुषार्थी और व्यहारकुशल पुलिस अधिक्षक श्री मदन कुमार आनन्द के साथ केवल सच मासिक पत्रिका के विशष प्रतिनिधि प्रो0 रामजीवन साहु ने साक्षात्कार किया।

मदन कुमार आनन्द का जन्म मुंगेर जिला में हुआ है। ये इतने ईमानदार और सहज दिखते हैं कि कहीं कोई पैरवी लेकर न आ जाय,इसलिए उन्होने अपने गांव का नाम नहीं बताए। जिस समय मैं उनसे साक्षात्कार के लिए गया, उस समय उनके कार्यालय में जनता दरबार लगा हुआ था। उस समय मैंने उनको देखा कि फरयादियों के साथ वे अत्यंत मधुर वाणि में बोल रहे हैं, परन्तु फरियादी सम्बंधित थाने को जिसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किये,उनको करक स्वर में उन्हें कर्तब्यों का बोध करा रहे थे। उनके पास समय का अभाव था,इसलिए वे मेरे प्रश्नों के उत्तर हां या नहीं में दे रहे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर से ही प्राप्त हुई। बी0 टेक, नीट और एम0 टेक की पढ़ाई पटना में हुई। जब पूछा गया कि पत्रकार के बारे में आपकी क्या धारना है, तो उनका उत्तर मिला कि पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। पत्रकार दुनियां का सबसे अच्छा तंत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। आजकल तो गांव,शहर,देश और दुनियां की जानकारी प्रिंट मीडिया और इल्कटरोनिक मीडिया से ही मिलती है। अत: पत्रकार बंधु लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। इनके अच्छे कार्यों के लिए कोटि-कोटि बधाई और ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ●

सीएम नीतीश ने किया चक्रवर्ती सम्राट जरासंध की प्रतिमा का लोकापर्ण

● **अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह**

अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में मगध के चक्रवर्ती सम्राट जरासंध के स्मारक का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। साथ ही जू सफारी में बना एवीयरी का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर जीविका दीदीयों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत किया गया। साथ में दोनो उपमुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर जरासंध स्मारक स्थल को रंग-बिरंगे फूलों और विविध प्रकार के पौधों से सजाया गया है।

जिसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। ब्रास मेटल से यह निर्मित यह स्मारक अत्यंत आकर्षक है। इस मूर्ति के निर्माण पर 14.83 करोड़ रूपए की लागत आई है। इस जरासंध स्मृति पार्क में मगध सम्राट की 21 फीट उँची आदमकद प्रतिमा को 11 फीट उंचे पेडेस्टल पर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 27 नवंबर 2022 को गंगाजल आपूर्ति योजना के उद्धाटन के अवसर पर जरासंध स्मारक के निर्माण की घोषणा की थी, जिसे शनिवार को पूरा कर दिया गया। बताया गया कि जरासंध बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। और मल्ल युद्ध में निपुण थे। उन्होनें अपने को एक कुशल राजकुमार के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा बृहद्रथ ने अपनी सारी जिम्मेदारियां जरासंध को सौंप दिए और स्वयं रानियां के साथ वनवास के लिए चले गए। चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा में जरासंध ने अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित किया लेकिन उन्होनें पराजित राजाओं को मारा नहीं बल्कि बंदी बनाकर रखा ताकि जब 101 राजा हो जाए तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। जरासंध महादेव के अनन्य भक्त थे। ब्राहम्णों का आदर करते थे। दान पुणय में विश्वास रखते थे और अपने वचन के पक्के थे। नवनिर्मित जरासंध स्मारक राजगीर में भ्रमण करने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस स्मारक के माध्यम से नई पीढ़ी को प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ0 प्रेम कुमार ने कहा कि चन्द्रवंशियो का गौरवशाली अंतित रहा है। जरासंध की भुजाओं मे दस हजार हाथी का बल था। इतिहास गवाह कि चन्द्रवंशियो का मगध पर 5000 ई तक शासन रहा है। उन्होने अपना पराक्रम से भगवान कृष्ण को 17 वार हराया और रणछोड़ की उपाधी श्री कृष्ण को दी। साथ ही भारत तथा अन्य देशों के 275 राजाओ को वंदी बनाया। महाभारत चन्द्रवंशियो का इतिहास रहा है। जरासंध का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली महाभारत काल से ही रहा है।

भितिचित्र से जान सकेगे चक्रवर्ती सम्राट जरासंध की जीवनी साथ ही एक एकड़ मे फैली पक्षीशाला में देश विदेशी प्रजाति की पक्षियो का पक्षीशाला का किया लोकापर्ण किया साथ ही माता जरा देवी मंदिर का होगा सौदर्यीकरण से पर्यटन को मिलेगी उड़ान तो स्थानीय लोगो को मिलेगी रोजगार। अखण्ड भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट मगध सम्राट महाराज जरासंध धाम की नगरी राजगृह में सम्राट जरासंध स्मारक का लोकापर्ण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा किये जाने पर चन्द्रवंशियो मे हर्ष की लहर दौड़ पड़ी सम्राट जरासंध स्मारक में महाभारत काल के महान सम्राट जरासंध की 21 फीट उंची प्रतिकात्मक प्रतिमा जरासंध की जीवनी पर, भिति चित्र, जरासंध जानकारी केन्द्र जल सरक्षण संरचना तथा पार्क का निर्माण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री डॉ0 प्रेम कुमार समेत चन्द्रवंशी समाज के बड़े नेताओं एवं चन्द्रवंशियो के सघर्ष के पहल पर सपना

साकार हो सकी। इससे राजगीर आने वाले पर्यटको को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी मिलेगी। साथ ही उन्होने कहा कि डॉ0 प्रेम कुमार के नेतृत्व में इसके लिए लम्बे समय से चन्द्रवंशी समाज का सघर्ष जारी था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मे मंत्री रहते हुए विभागीय औपचारिकता पूरी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देकर समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही उन्होने कहा कि जरासंध के जन्मदिवस पर जेठान पर्व मनाया जाता है और शिव समेत 84 करोड़ देवी देवताओं को राजगृह मे उतारने वाले जरासंध तब ही से मलमास मेले का आयोजन होने लगा। छठ पर्व भी जरासंध का ही देन है। महाभारत चन्द्रवंशियो का इतिहास रहा है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ सुनील कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार, राजगीर विधायक कौशल कुमार आदि मौजुद थे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाले अजय कुमार बनिया विगहा मुखिया पंकज सिंह, मनोज चन्द्रवंशी, डॉ0 के0पी0सिंह, डॉ0 परमानन्द चन्द्रवंशी युवा नेता लवकुश कुमार, मोहन सिंह, प्रिंस कुमार, चन्दन कुमार, अरविन्द सिंह, श्याम किशोर भारती, मिलन सिंह समेत कक्ष गणमान्य लोग उपस्थित थे।●

महाशिवरात्री पर भव्य मंडप शिव नाम संकीर्तन का भव्य आयोजन

● **अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह**

नवादा जिलो मे शंकुतलम नगर में महाशिवरात्री के अवसर पर दो दिवसीय भक्तिमय आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह हर हर महादेव हर शिव: हर हर नम: शिवाय से गुंजा नवादा शहर नवादा महाशिवरात्री के सुभ अवसर पर संकीर्तन (अष्टजाम) भवय आयोजन मे हजारो-हजार की संख्या मे शिव शिष्ट परिवार के गुरू भाई एवं बहनो का भक्तिमय जन सैलाव आया। इस दो दिवसीय भक्तिमय आयोजन से पहले दिन महादेव का भव्य मंडप बनाकर उसे तरह-तरह की फूलो से सजाकर अमरनाथ के शिव का रूप दिया गया। वनारस से आये पाँच ब्राहमणो की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन कराये। इस दौरान रूद्राभिषेक भी हुआ। इस पूजन में मनोज कुमार मन्टु भजमान के रूप मे शामिल हुए। श्रद्धालु विजय कुमार ने बताया कि इस आयोजन मे शामिल होने के लिए हरके साल नवादा जिले के गॉव-कस्वो के अलावा गया, पटना, कोलकता, राँची, दिल्ली, मुम्बई, वर्द्धमान व दूसरे जगहों से भी सैकड़ो श्रद्धालु इस बार पहुँचे हुए है। सुबह सात बजे से पूजन शुरू हुआ। जो करीब 12 बजे तक चला इसके बाद हर-भोला हर भोला, भोला-भोला हर हर का संकीर्तन जाप शुरू हुआ। यह जाप निरंतन रात से लेकर सुबह तक चलता रहा।

27 फरवरी को श्रद्धालुओ के बीच चावल को महाप्रसाद वितरण गया। इसे पूरे आयोजन में दिल्ली के नारायण बसकोटा, पिंटु कुमार, प्रभारी उदय कुमार, श्रद्धालु रंधीर कुमार की संख्या मे महिला श्रद्धालु मौजुद थे। इसके पहले ढोल बाजो के साथ शिव की बारात निकाली गई। नवादा के शहर में बारात को घुमाया गया। इसके वाद कार्यक्रम का समापन किया गया।●